प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ..सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

दुख और वेदना के अथाह सागर वाले इस संसार में प्रेम की अत्यधिक आवश्यकता है।

डॉ. रामकुमार वर्मा

वर्ष-07, अंक - 43 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 24 जुलाई 2025 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

संसद में भी सड़क जैसा हंगामा, सांसदों पर गुस्साए लोकसभा अध्यक्ष

नई दिल्ली, एजेंसी।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को संसद में विपक्ष के शोर-शराबे पर नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने विपक्षी सांसदों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आप संसद में भी सड़क जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सदन में तख्तियां दिखाने को लेकर सख्त चेतावनी दी।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होते ही आरंभ हुआ।

विपक्षी सांसद पोस्टर और तख्तियां लेकर लोकसभा में अध्यक्ष के आसन के समीप आ गए और नारेबाज़ी करने लगे। इस पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सख्त लहजे में कहा, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी।

प्रश्नकाल के शुरुआती कुछ मिनटों में रेल मंत्रालय से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा हुई, किंतु हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष बिरला विपक्षी सांसदों पर भड़क गए। उन्होंने कहा, संसद हमारे लोकतंत्र की गौरवशाली संस्था है मैं, सभी से आग्रह करता हूं कि संसद के भीतर आपका आचरण और कार्यपद्धति मर्यादित होनी चाहिए। देश की जनता ने आपको यहां उनकी आवाज़ उठाने, समस्याओं और नीतियों पर चर्चा के लिए भेजा है। आप सड़क जैसा व्यवहार संसद में कर रहे हैं, जिसे पूरा देश देख रहा है।

अध्यक्ष ने विपक्ष के नेताओं से आग्रह किया कि, वे अपनी सीट पर जाकर बैठें और मुद्दों पर चर्चा करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर विषय पर नियमों के तहत संवाद और चर्चा का पूरा अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा, आप माननीय हैं, तो फिर वैसा आचरण भी करें। गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। पहले दिन विपक्ष ने 'ऑपरेशन सिंदूर' और पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर हंगामा किया। दूसरे दिन बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विरोध दर्ज कराया गया।

तन्वी द ग्रेट हुई कर मुक्त

भोपाल। अनुपम खेर के निर्देशन में बनी फ़िल्म तन्वी द ग्रेट को मध्य प्रदेश सरकार ने कर मुक्त घोषित कर दिया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फ़िल्म देखने के उपरांत की। अनुपम खेर, जो फ़िल्म में एक कलाकार की भूमिका में भी हैं, ने सामाजिक मंच पर मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।

अनुपम खेर ने लिखा- आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी! आज भोपाल में पहले आपके निवास स्थान पर भेंट हुई। उसके बाद यह हमारा सौभाग्य रहा कि, आप हमारी फ़िल्म तन्वी द ग्रेट को चलचित्र गृह में देखने पधारे। आपने न केवल हमारी फ़िल्म की सराहना की, बल्कि इसके जज़्बे को देखकर इसे कर मुक्त घोषित कर दिया। यह आपके सामाजिक विषयों एवं सेना के प्रति विशेष संवेदनशीलता को दर्शाता है। एक बार पुनः आपका, आपके मंत्री परिषद एवं अन्य अधिकारियों का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद! इस फ़िल्म में अनुपम खेर के अतिरिक्त जैकी श्रॉफ, अरविंद स्वामी, बोमन ईरानी, पल्लवी जोशी, करण टैकर और नासर जैसे कलाकारों ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं।

उपराष्ट्रपति का इस्तीफा: असंतोष की शुरूआत या स्वास्थ्य का बहाना...?

माही की गूंज, संजय भटेवरा।

नई दिल्ली। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में पिछले दो कार्यकाल की अपेक्षा कमजोर सरकार है। हालांकि भाजपा अब भी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है लेकिन पूर्ण बहुमत से दूर ही है। अब तक शीर्ष नेतृत्व के हर फैसले को पार्टी की अन्य छोटी इकाई अक्षरशः पालन करते नजर आई है। यही नहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में कई बार अप्रत्याशित फैसले लेते हुए न केवल राजनीतिक पंडितों को चौंकाया है वरन आम जनता को भी अचंभित किया ह। चाहे वह राजस्थान में पहली बार बने विधायक को मुख्यमंत्री बनाना हो या मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चयन हो, हर बार शीर्ष नेतृत्व ने लिक से हटकर फैसले लिए और पूरी एक जुटता के साथ लागू किए। लेकिन वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक अप्रत्याशीत कदम उठाते हुए मानसुन सत्र के पहले ही दिन अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है जो कि राजनीतिक पंडितों के लिए शोध का विषय बन गया है। हालांकि किसी भी व्यक्ति का अपने पद पर रहना या नहीं रहना उसने स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है और जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया है। लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि, स्वास्थ्य तो केवल बहाना असली कहानी तो पर्दे के पीछे की है जिसको निर्वतमान उपराष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार के साथ ताल मेल न बैठ पाना है। जिसको लेकर वे अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे।

वहीं कई लोगों का मानना है कि, यह नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ असंतोष की चिंगारी है तो देर सवेर भड़क भी सकती है। क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और वर्तमान में मोदी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। विपक्ष हमेशा से ही मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाती रही है लेकिन कमजोर संख्याबल के आगे विपक्ष की आवाज उतनी धारदार नहीं रही लेकिन उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का एक और मुद्दा मिल गया। हालांकि विपक्ष अभी भी इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि, वो मोदी सरकार को अस्थिर कर सके। लेकिन इस मुद्दे को वो सरकार के खिलाफ भुना अवश्य सकता है और आम जनता में यह संदेश पहुंचा सकता है कि, मोदी सरकार के फेसलो पर असंतोष उभरने लगा है।

इस्तीफे पर कई सवाल

दिन भर कोई व्यक्ति अपने काम में मशगुल रहे और रात में अचानक अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए त्यागपत्र दे दे तो यह बात आम जनता को भी हजम नहीं होती है। और जब मामला देश से जुडा हो तो सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ...? उपराष्ट्रपति के मामले में भी ऐसा ही हुआ क्योंकि वे सदन में दिन भर सक्रिय थे और रात को अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। हालांकि स्वास्थ्य का कारण व्यक्तिगत कारण है और वह चर्चा का विषय नहीं बनना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर कई सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों के जवाब आम जनता को मिलना चाहिए। लेकिन यह कहा नहीं जा सकता है कि, सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे...?

आम लोगों का मानना है कि, जगदीप धनखड़ एक तेज तर्राट और बेबाक नेता है ऐसे में वे केंद्र सरकार के हर फैसलों को मौन समर्थन नहीं दे सकते थे। विभिन्न मुद्दों पर पिछले दिनों उन्होंने सरकार के प्रतिकुल वक्तव्य देने में संकोच नहीं किया था। यही नहीं वे सुप्रीम कोर्ट को भी निशाने पर ले रहे थे। वे पेशे से वकील थे इसलिए उनकी कानूनी समझ को नकारा नहीं जा सकता था। विभिन्न विषयो पर उनकी बेबाकी सरकार के साथ ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को भी रास नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक घटे इस घटनाक्रम के बाद जो कांग्रेस उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने का मन बना रही थी वहीं कांग्रेस उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद उन्हें अचानक नेक, विनम्र, निष्पक्ष और गुणी बताने में जुड़ गई। इसलिए कहा गया है कि राजनीति में न कोई स्थाई दोस्त होता है और न ही स्थाई दुश्मन।

बहरहाल उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के तत्कालीक रूप से कोई राजनीतिक हलचल नहीं होगी लेकिन इसके दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से सामने आएंगे। और कई राजनीति पंडित इसे मोदी सरकार के खिलाफ असंतोष की शुरुआत भी कह रहे हैं। अब आगे क्या होता है यह तो भविष्य के गर्भ में है।

सुनवाई से मुख्य न्यायाधीश गवई ने खुद को किया अलग

नई दिल्ली, एजेंसी।

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक संवेदनशील और चर्चित याचिका पर सुनवाई उस समय टल गई जब भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा से जुड़ा है, जिन्होंने अपने खिलाफ गठित आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

मुख्य न्यायाधीश गवई ने स्पष्ट किया कि वे न्यायमूर्ति वर्मा की नियुक्ति करने वाले कॉलेजियम में शामिल थे, इसलिए नैतिकता की दृष्टि से इस याचिका पर सुनवाई करना उचित नहीं होगा। जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस याचिका पर

शीघ्र सुनवाई की मांग की, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अब इस मामले को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

ज्ञात हो कि न्यायमूर्ति वर्मा ने उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका में उस जांच रिपोर्ट को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें नगदी बरामदगी मामले में दोषी बताया गया था। घटना के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी, जिसने 10 दिन तक जांच कर 55 गवाहों से पूछताछ की थी। समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि जिस स्थान पर आग लगी और नगदी मिली, उस पर वर्मा और उनके परिवार का प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण था। रिपोर्ट के अनुसार, यह आचरण इतना गंभीर है कि उन्हें न्यायाधीश पद से हटाने की सिफारिश की जानी चाहिए।

इस रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर महाभियोग चलाने की अनुशंसा की थी। अब न्यायमूर्ति वर्मा ने याचिका दायर कर इस जांच की निष्पक्षता, प्रक्रिया और निष्कर्षों पर सवाल उठाए हैं।

धनखड़ के इस्तीफ़े पर खड़गे ने कहा दाल में है कुछ काला

नई दिल्ली, एजेंसी।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा अचानक दिए गए इस्तीफ़े ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखे सवाल दागते हुए कहा कि जब धनखड़ जी पूरी तरह स्वस्थ थे, तब उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया? खड़गे ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह केवल स्वास्थ्य कारणों का मामला नहीं लगता, बल्कि इसमें कुछ छिपा हुआ है। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि दाल में कुछ काला है।

खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार को देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफ़ा क्यों दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कोई अंदरूनी कारण है जिसे जनता से छिपाया जा रहा है? खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि जगदीप धनखड़ हमेशा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भाषा बोलते थे। उन्होंने कहा कि वे कभी भी विपक्ष की बातों का समर्थन नहीं करते थे और उनकी पूरी निष्ठा सत्ता पक्ष के साथ रही।

उन्होंने कहा कि, जब ऐसे व्यक्ति अचानक पद छोड़ते हैं, तो यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों का भी मानना है कि यह इस्तीफ़ा केवल स्वास्थ्य संबंधी कारणों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव या रणनीति हो सकती है। अब तक केंद्र सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई ठोस या विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

धनखड़ ने 22 जुलाई की रात उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा दिया था। अपने पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का उल्लेख किया, जबकि उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था।

शराब छुड़ाने की शपथ दिलाई गई गड़ावदिया के बालाजी धाम पर

चौमुही दिखावटी भक्तो से बचना आवश्यक

माही की गूंज, रतलाम/ गड़ावदिया

यह अलग बात है कि, भक्तों द्वारा अपनी आस्था पर परिवर्तन कर भगवान को ही बदल दिया जाता है। तथा ऐसे भक्त जो भेड़ की चाल की तर्ज पर स्थान को बदल-बदल कर अपनी आस्था, अपनी स्वार्थ पूर्ति के साथ बदले जाते हैं। ऐसे दिखावटी भक्तों की उपस्थिति भी एक धार्मिक स्थान की विश्वनीयता में सेंध लगाने का प्रयास भी ऐसे चोमुही दिखावटी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।

ऐसे चौमुही दिखावटी भक्तों से धार्मिक स्थान के मठाधिशों को भी बचने की आवश्यकता है। वर्तमान में रतलाम जिले के गड़ावदिया में बालाजी धाम के नाम से प्रसिद्धि क्षेत्र के साथ गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र तक हासिल कर रहा है। कहा जा रहा है कि, गडावदिया ग्राम पंचायत में गड़ावदिया के साथ कुल चार गांव लिम्बापाड़ा, रूपापाड़ा व हवारून्डी है। उक्त क्षेत्र में चुनावी माहौल के दौरान ही जिले व बाहरी जननेता आते थे।

उसके अलावा कोई भी इस क्षेत्र की सुध नहीं लेता था लेकिन वर्तमान में गड़ावदिया के बालाजी धाम मंदिर के मठाधीश श्रीधर बैरागी मंगलवार व शनिवार को दरबार का आयोजन करते हैं। उक्त दरबार में भी भिन्न-भिन्न तरह की प्रतिक्रिया भी दी जाती है जो हर जगह देखने में आती है। लेकिन वर्तमान में देखने में आ रहा है कि, कई बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति रतलाम, झाबुआ जिले के अलावा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के लोग भी मठाधीश श्रीधर बैरागी के दरबार में पहुंच रहे हैं और अपने समाधान एवं बीमारी में सुधार की भी बात कर रहे हैं। उक्त मठाधीश श्रीधर बैरागी कथा का आयोजन भी करते हैं तथा धार्मिक विचारों को प्रसारित करने के साथ श्रीधर बैरागी समाज में समरसता, नशा करने वाले नशा से मुक्त हो व अपराध करने वाले अपराधी अपराध से दूरी रखें का प्रयास भी कर रहे हैं। इसी तारत्म्य में झाबुआ जिले की जेल में भी कथा का वाचन श्रीधर बैरागी कर चुके हैं। वहीं अन्य जिले में भी उनकी कथा का वाचन हो और आपराधिक मानसिकता खत्म नहीं तो कम हो की विचारधारा श्रीधर बैरागी की है। वही इन्हीं प्रयासों के साथ अब गड़ावदिया के दरबार में वर्तमान स्थिति में भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। वही जाने-माने जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी व बड़े व्यापारी भी उक्त धाम पर पहुंचने लगे हैं।

मंगलवार को गड़ावदिया पंचायत के लिम्बापाडा में हनुमान मंदिर पर हवन-पाठ कर दरबार का आयोजन किया गया। उक्त दरबार में भी बीमारी से ग्रस्त कई लोग हर मंगलवार की तरह पहुंचे जिनका उपचार किया गया। और जब लोगों द्वारा उन बीमारी से ग्रस्त लोगों से पूछा गया कि, यहां आने पर बीमारी में सुधार होता है या नहीं..? जिस पर जवाब मिला कि, यहां आने पर बीमारी में सुधार हो रहा है और कइयों की बीमारी भी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। वहीं गृहस्थ जीवन में अन्य समस्याओं का समाधान भी दरबार में श्रीधर बैरागी के द्वारा किया जा रहा है। मंगलवार को लिम्बापाडा में दरबार शुरू करने के पूर्व करीब 30 से अधिक व्यक्तियों के शराब नशे से मुक्ती के साथ किसी भी प्रकार का नशा एवं बीड़ी, सिगरेट नहीं पीने की शपथ श्रीधर बैरागी ने दिलाई। शपथ के द्वारा मठाधीश श्री बैरागी ने नशा मुक्ति से शपथ लेने वाले को कहा कि, भगवान बालाजी के समक्ष शपथ लेकर हम नशा मुक्त हो रहे हैं ऐसे में कोई शपथ लेने वाला नशा करता है तो उसके टापरे भी बिक जाएंगे। ऐसे में श्रीधर बैरागी ने संदेश देते हुए स्पष्ट कहा कि, कोई भी व्यक्ति बालाजी भगवान के सामने नशा मुक्ति की शपथ लेने के बाद नशा नहीं करें।

वहीं वर्तमान में प्रसिद्धि हासिल करने वाले उक्त स्थान पर भी उन चौमुही लोगों की भी उपस्थिति देखी जा रही है जो कभी रोग्या देवी के भक्त थे, तो कभी खाटू श्याम के अट्ठू भक्त, तो कभी अन्य भगवान के ऐसे भक्त की वह भक्त अन्य किसी भगवान को मानता ही नहीं सिर्फ वही भगवान उसके आराध्य देव भगवान है। एवं उन भगवान के नाम के बैनर तले धार्मिक आयोजन भी इस तरह से करवाए गए कि, भगवान नहीं वे ही सब कुछ है। वे चौमुही भी अब गड़ावदिया जाकर मठाधीश श्रीधर बैरागी के सामने ऐसा दर्शा रहे हैं कि, अब उनके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसे में श्रीधर बैरागी के साथ उन सभी मठाधिशों को ऐसे चौमुही दिखावटी भक्तों से दूरी बनाए रखना चाहिए यह चर्चा यहां होने लगी है, ताकि यह किसी भी भगवान के पवित्र स्थान में इनकी अपवित्रता ना फैला सके।

मठाधीश श्रीधर बैरागी बालाजी दरबार में मरिजो का उपचार व समाधान करते हुए।

- शराब व अन्य नशा नही करने की मठाधीश ने हवन कुंड के आगे दिलाई शपथ।

धार-झाबुआ सीमा पर माही नदी के राजघाट पर पुल निर्माण की स्वीकृति से एक ओर मालवा का द्वार खुला

5.89 करोड़ रुपये से होगा निर्माण, सफर, समय और ईंधन की होगी बचत

माही की गूंज बरवेट।
जगदीश प्रजापति

धार- झाबुआ की सीमा पर बह रही माही नदी के राजघाट पर पुल निर्माण के लिए स्वीकृति मिल गई है। टेंडर लगने के बाद इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इस नदी पर पुल निर्माण का निर्णय दो जिलों के बीच आवागमन को सूगम बनाने और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। क्षेत्रवासियों का मानना है कि, पुल निर्माण से मालवा के लिए एक ओर प्रवेश द्वार खुल जायेगा। पेटलावद से राजोद का सफर भी 13 किलोमीटर एव माही किनारे रहने वाले ग्रामीणों के लिए राजोद की दूरी लगभग 35 किलोमीटर तक कम हो जाएगी।

गौरतलब है कि, क्षेत्रवासियों द्वारा पुल निर्माण की मांग पिछले दो दशक से की जा रही थी। जिस पर केबिनेट मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने विभाग से प्राकलन बनावकर पिछले बजट में लेकर पांच करोड़ 89 लाख रुपये मंजूर करवाकर प्रशासकीय स्वीकृति दिलवाई। बताया जाता है कि, बरसात के दिनों में यह मार्ग बंद हो जाता है। इस मार्ग पर एक रपटा बना हुआ है। वह भी जर्जर हो चुका है।

सफर होगा आसान

माही नदी पर पुलिया निर्माण होने से निश्चित रूप से लोगों का सफर आसान होगा, ईंधन ओर समय की बचत एवं यात्रा सुगम होगी। वर्तमान में माही नदी पर रपटा बना हुआ है।

वरसिंग कटारा ग्रामीण माही नदी क्षेत्र नरसिंहपूरा ने बताया कि, बरसात में आवागमन बंद हो जाता है। माही नदि क्षेत्र के ग्रामीणों को राजोद जाने के लिए थांदला-बदनावर मांग का उपयोग करते है। जो कि लगभग 36 किलोमीटर पड़ता है। पुल निर्माण के बाद राजोद की दुरी सात किलोमीटर रह जाएगी।

एक नजर में स्थिति

- वर्तमान में पेटलावद से राजोद- 43 किलोमीटर।
- पुल निर्माण के बाद पेटलावद से राजोद की दूरी-32 किलोमीटर।
- पुल निर्माण की लागत- 5 करोड़ 89 लाख रुपये।
- पुल की लंबाई- 150 मीटर।
- पुल की चौड़ाई- 8.40 मीटर।
- पुल की ऊँचाई- 20 फ़ीट लगभग।

संजय परमार और नवींचन्द सिह राठौर भाजपा नेता ने बताया कि, माही नदी पर पुल निर्माण होने के बाद यात्रा का समय व दूरी कम हो जाएगी, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी। वर्तमान में पेटलावद व्हाया सारंगी, भेसौला चौपाटी होकर राजोद पहुचने के लिए लगभग 43 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। वही पुल निर्माण होने के बाद यह दूरी 33 किलोमीटर रह जाएगी। जिससे लगभग 10 किलोमीटर का सफर कम होगा, समय और ईंधन की बचत होगी। माही नदी पर पुलिया निर्माण का सपना पिछले तीन दशक से देख रहे थे, जो अब साकार हो जाएगा। पुल निर्माण होने से एक ओर नया मालवा का द्वार खुल जाएगा। वही दोनों जिलों के बीच व्यापार और व्यवसाय की गतिविधियां भी बढ़ेंगी। पुल निर्माण की मंजूरी के साथ-साथ पेटलावद से राजोद मार्ग का चौड़ीकरण की वकायद भी शुरू करनी चाहिए।

दिलीप चौहान लोकनिर्माण विभाग झाबुआ ने बताया कि, झाबुआ-धार की सीमा पर माही नदी राजघाट पर पुल निर्माण के लिए 5.89 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए है। जिसके निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है। टेंडर लगने के बाद कार्य प्रारंभ होगा।

केबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि, विकास ही हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। पिछले दो-तीन दशकों से जनहितैषी मांगे है, उनको पूरा करना हमारा लक्ष्य है। पुल निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। रही बात राजोद, बरवेट, पेटलावद मांग चौड़ीकरण के लिए प्रयास किए जाएंगे।

बम बम, भोले शंभू भोलेनाथ के जयकारों के साथ निकली कावड़ यात्रा

माही की गूंज, भामल।

सावन महीने में इन दिनों कावड़ यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जा रही है। जिसमें बड़ी संख्या में भोले के भक्त बोल बम, बोल बम, के जयकारो के साथ भोले की फौज करेगी मौज की धूम से कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। मंगलवार को 9 बजे ग्राम भामल में ही पथवारी वाले कुएं से कावड़ में पानी लेकर राजपूत युवा संगठन द्वारा आयोजित भव्य पैदल कावड़ यात्रा भामल से उज्जैन के लिए रवाना हुई। जिसमें बड़ी संख्या में भामल के साथ ही आस-पास के कावड़ियों का कावड़ यात्रा में सम्मिलित हुए। वहीं आस-पास चौराहे से कावड़ यात्रा में जा रहे यात्रियों पर पुष्प वर्षा भी खवासा व भांमल में की गई। बताते है भामल में प्रतिवर्ष सावन माह में इसी तरह से कावड़ यात्रा निकाली जाती है जो पैदल चलकर उज्जैन में महाकाल भगवान को जल अभिषेक करते है। कावड़ यात्रा में सम्मिलित कैलाश नकुम, कमल चावड़ा, कमलेश गहलोत, रामसिंह पालरा, केशव सोलंकी आदि ने बताया कि, 22 जुलाई 2025 मंगलवार को सुबह से कावड़ में जल भरकर कावड़ यह पैदल चलकर उज्जैन में 26 जुलाई 2025 शनिवार को जलाभिषेक महाकाल को अर्पित करेंगे। सभी कावड़िये बड़ी ही धूमधाम से यात्रा में सम्मिलित हुए सभी कावड़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था में तीन हलवाई के साथ खाने-पीने की सभी सामग्री ट्रक में व डीजे भी साथ मे है। वहीं रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी समिति द्वारा आगे जाकर की जा रही है। वही ट्रक की व्यवस्था खवासा के संतोष पाटीदार ने कावडीयों के लिए फ्री-सुविधा उपलब्ध करवाई है।

श्रृंगेश्वर महादेव तक भव्य कावड़ यात्रा

माही की गूंज, पेटलावद/बनी।

अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के ग्राम बनी समिति ने ग्राम बनी शिव मन्दिर से सभी कावड़ियों को जल भर कर जय भोलेनाथ, हर-हर महादेव के नारों से धूमधाम से कावड़ यात्रा का आरंभ किया और कावड़ यात्रा का समापन श्रृंगेश्वर महादेव पर जलाभिषेक कर किया। हजारों महिला, पुरुष, युवक युवतीयो ने श्री महादेव पर जल चढ़ाकर अपनी मन्नत पूरी की। श्रृंगेश्वर महादेव धाम झकनावद महंत श्री रामेश्वर गिरी महाराज ने सभी कावड़ यात्रियों, महिला मातृशक्ति को अपने आशीर्वचन दिया। कावड़ यात्रा का स्वागत अनेक स्थानों पर किया।

मनाई पुण्यतिथि

माही की गूंज, थांदला।

प्राचीन हनुमान अष्ट मंदिर भक्त मलूकदास की बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध बावड़ी मंदिर के महंत राष्ट्रवादी संत 1008 साकेतवासी नागा देवनारायणदासजी महाराज की 32 वीं पुण्यतिथि, न्यास मंडल तथा भक्तजनों द्वारा उनके समाधिस्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके जयकारों के साथ मनाई गई।

ट्रस्ट अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने बताया कि, नागा देवनारायणदासजी ने आजादी के पूर्व से ही अपने जीवन को मानव सेवा में समर्पित करते हुए जीवन को समस्त देशवासियों में राष्ट्रवाद का बीजारोपण करते हुए उन्हें स्वधर्म संस्कृति पर अडिग रहने के लिए प्रेरित किया। आप गौ रक्षा आंदोलन, गौ मुक्ति आंदोलन, कच्छ रण मुक्ति आंदोलन, बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। साथ ही संपूर्ण वनांचल में गंगा यात्रा से लेकर राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए आई शिला पूजन यात्रा तक को जन समुदाय के लिए एकात्मता आंदोलन में प्रेरणा स्त्रोत बने परिणाम स्वरूप आपको पूरे 19 महीने मीसा कानून के तहत जेल में रहना पड़ा। आयोजन में विधायक वीरसिंह भूरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष सोनल भाबर, समाजसेवी कांग्रेस के प्रदेश संयोजक जसवंत भाबर, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील पणदा, भाजपा मंडल अध्यक्ष बंटी डामोर, पत्रकार अक्षय भट्ट, वार्ड पार्षद राजू धानक, पार्षद कन्नू मौर्य पार्षद, जगदीश प्रजापत, आदि ने भी महंत के ग्रामीण अंचल में सामाजिक योगदान के लिए उन्हें याद किया। इस अवसर पर मन्दिर के महंत नारायणदासजी द्वारा उनकी महाआरती की गई जिसमें अंचल के विभिन्न स्थानों से पधारें साधु संत भी शामिल हुए।

20 लाख के भवन में घटिया निर्माण का ग्रामीणों ने लगाया आरोप

भवन 2021-22 में स्वीकृत लेकिन अब भी कार्य अधूरा

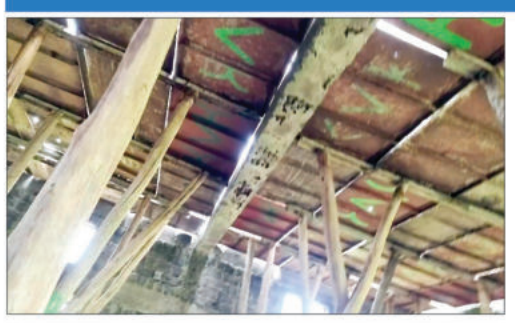

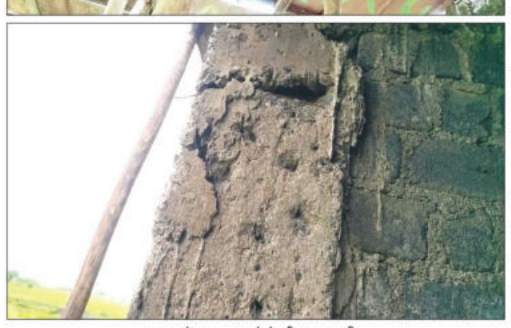

भवन में भ्रष्टाचार, फोटो की मुह जुबानी।

माही की गूंज, खवासा।

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अहम कड़ी ग्राम पंचायत होती है। जिसकी कल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी जो साकार तो हो गई पर अब यह व्यवस्था विकास करने की जगह जेब भरो का साधन बन चुकी है। गांव में विकास कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से ही होते हैं और ग्राम पंचायत ही सर्वेसर्वा होकर उस विकास कार्य की गाथा लिखती है। लेकिन ग्राम पंचायत अगर निष्क्रिय हो जाए और भ्रष्टाचार करने लगे तो ग्रामिणों की आस धरी की धरी रह जाती है।

कुछ ऐसा ही हो रहा है, थांदला जनपद की ग्राम पंचायत रन्नी मे। यहा के ग्रामीणों ने बताया कि, वर्ष 2021-22 में रन्नी ग्राम पंचायत का नवीन भवन स्वीकृत हुआ है। जिसकी लागत 20 लाख थी। भवन 2 साल में बनाकर पूर्ण निर्माण कर देना था। निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत थी लेकिन 2 साल से अधिक समय हो गया अभी तक भवन अधूरा पड़ा है। वही ग्रामीणों की शिकायत के बाद फिर से कार्य शुरू किया तो उसमें भी अन्य अनियमिताओ की शिकायत ग्रामीण करने लगे। ग्रामीणो का आरोप है कि अभी जो सेंटिंग लगाने के बाद छत भराई का कार्य चल रहा है। उसमें 12 एम, एम के सरिया लगाने के बजाय 8 से 10 एम, एम के सरिये के साथ ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। तो वहीं भवन भी घटिया निर्माण के साथ बनाया जा रहा है आसपास गिट्टी जो पड़ी हुई है वह भी मिट्टी से लदी हुई है जो साफ तौर पर निर्माण के नाम पर घटिया निर्माण किया जा रहा है दर्शा रहा है।

एक तरफ प्रदेश सरकार जीरो टारलेंस की नीति अपना कर भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा कर रही है। यहां रन्नी ग्राम पंचायत की तर्ज पर खुले आम भ्रष्टाचार किया जा रहा है लेकिन जिसे देखने वाला तक कोई नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि, जब से भवन बनाया तब से सामग्री में निम्न स्तर का इस्तेमाल किया गया है। शासन अगर 20 लाख की लागत से निर्माण करवा रहा है तो उसका सही इस्तेमाल निर्माण के वक्त होना चाहिए लेकिन ऐसा रन्नी पंचायत में होता नहीं दिख रहा है। जो पिलर भरे गए हैं उसमें भी सरिया आदि दिख रहे हैं। जिसमें सीमेंट और गिट्टी का घोल सही नहीं लगाया गया है। कोई सीनियर इंजीनियर अगर भवन की जांच पड़ताल करें तो काफी अनियमिता भवन में मिलेगी यह ग्रामीणों का कहना है।वही ग्रामीण जांच की मांग कर रहै है।

मामले में तत्कालीन इंजीनियर आनंद तिवारी से चर्चा की उन्होंने बताया कि, यह भवन मेरे कार्यकाल का ही है लेकिन मेरा तो वहां से ट्रांसफर हो चुका है, यह भवन अभी भी अधूरा है वहां कार्य सही नहीं हो रहा है यह मैं भी जानता हूं... लेकिन अब मैं क्या कर सकता हु मेरा तो ट्रांसफर हो चुका है, इस मामले में आप वर्तमान इंजीनियर अतुल डामर से चर्चा कर ले।

वही मामले में वर्तमान इंजीनियर अतुल डामर से चर्चा की उन्होंने बताया कि, मेरे पास भी रंन्नी पंचायत की काफी शिकायत ग्रामीणों द्वारा मिली है। मैं, खुद मामले को देखने जाऊंगा की भवन में किस तरह का कार्य व निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद जो भी होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटिया निर्माण से कार्य नहीं होने दिया जाएगा।

एमपी मे खाद नही मिल रहा लेकिन समीपस्थ बड़ीसरवा (राज.) से व्यापारी धड़ल्ले से 430 में खाद की बोरी एमपी के किसानो को दे रहे

माही की गूंज, खवासा/भामल।

भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, वही देश की 80 प्रतिशत आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार कई दावे तो करती है। लेकिन किसानो की समस्या व परेशानी आज भी बनी हुई है। हम पश्चिम क्षेत्र में बसे झाबुआ जिले की ही बात करें तो यहां किसाने की अपनी समस्या एक अलग ही बनी हुई है। तो वही जिले के कृषि अधिकारी खाद की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है इसका हवाला दे रहे हैं। लेकिन ग्रामीण अंचलों में आज भी किसान महंगे दाम पर यूरिया खाद की बोरी लाने को मजबूर है। अगर स्थानीय व्यापारियों के पास यूरिया खाद उपलब्ध नहीं है तो समीपपस्त राजस्थान से भी कई किसान महंगे दाम पर खाद लाने को मजबूर हो रहे हैं।

कुछ ऐसा ही मामला खवासा के आसपास किसानों का बना हुआ है। किसानों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि, खवासा व आसपास कहीं भी यूरिया की बोरी हमें समय पर व निर्धारित भाव नहीं मिल पा रही है। वही जिन किसानो का सहकारी सोसायटी में खाता नहीं है उनको भी खाद सोसाइटी पर नहीं मिल पा रहा है। जो किसान डिफाल्टर हो चुके हैं उनको भी सोसाइटी से नगदी में भी खाद नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में व्यापारियों की बल्ले-बल्ले हो रही है और महंगे दाम पर किसानों को खाद बेच रहे हैं। खवासा में दो दुकाने हैं एक संतोष पाटीदार एवं बलराम चौहान की जिनसे खाद का वितरण किया जाता है। लेकिन यहां भी स्टॉक नहीं होने के कारण आसपास के किसान समीपस्थ थांदला जनपद क्षेत्र की परवाड़ा पंचायत के अंतिम छोर पर राजस्थान की कुशलगढ़ जनपद की बड़ी सरवा के व्यापारी से महंगे दाम पर खाद लाने को मजबूर हो रहे हैं।

यह यूरिया बोरी खाद दिया जा रहा है राजस्थान के बड़ीसरवा से।

माही की गूंज को मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार बड़ी सरवा में कोई रवि टॉक करके व्यापारी है जो धड़ल्ले से किसानों को 430 रूपये में एक यूरिया बोरी उपलब्ध करवा रहे हैं। किसान मरता न क्या करता की तर्ज पर अपनी फसल के लिए महंगे दाम पर यूरिया खाद लाने को मजबूर है। जबकि सरकार कह रही है कि 266 रुपये में यूरिया खाद कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन यहां आस-पास किसानों से बड़ी सरवा का व्यापारी धड़ल्ले से 430 में एक यूरिया खाद की बोरी दे रहा है। अंदर की जानकारी रखने वाले बताते हैं। कि, यूरिया खाद की बोरी का व्यापारी ने काफी स्टॉक बड़ी सरवा में कर रखा है। सूत्र बताते हैं कि, व्यापारी रतलाम जिले के शिवगढ़ व आसपास से अवैध तरीके से यूरिया खाद की कालाबाजारी के साथ स्टॉक कर रहा है। बताते हैं की बड़ी सरवा में रवि टाक के यहां बांसवाड़ा के कृषि अधिकारियों ने छापा भी मारा था लेकिन क्या कार्रवाई हुई वहां स्थानीय मीडिया को भी कोई भी सूचना नहीं दी गई और मामले में लीपा-पोती हो गई।

किसानों का कहना है कि, अपने क्षेत्र में अगर खाद नहीं मिल रहा है तो वहां से लाकर भी फसल को तो देना ही पड़ेगा अब महंगा भी मिले तो क्या करें। खवासा व्यापारियों के पास जाते हैं तो उनके पास खाद है ही नहीं तो फिर क्या करें अब हमारी मजबूरी है।

वही मामले को लेकर व्यापारी रवि टाक से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि, मैं रतलाम जिले से खाद लाता हूं जो 350 रूपये में मुझे पड़ती है। खाद के साथ वहा से नैनो यूरिया भी देते हैं लेकिन हम नहीं लाते हैं इसलिए 350 रूपये में बोरी पड़ती है और यहां 430 में हम किसानों को दे रहे हैं, मेरे पास लाइसेंस तो नहीं है लेकिन आपके एमपी क्षेत्र के किसान अधिक आते हैं उनको कोई परेशानी ना हो इसको देखते हुए उनको यूरिया खाद हम दे रहे हैं।

वही मामले में थांदला व पेटलावद के कृषि विभाग के एसडीओ उदयसिंग काग से चर्चा की तों उन्होंने कहा कि, खवासा में दो व्यापारी ही यूरिया खाद थी दुकान संचालित करते हैं। एक संतोष पाटीदार (पटेल), बलराम चौहान लेकिन इन दोनों के पास अभी यूरिया खाद नहीं है। एक-दो दिन में रतलाम से रैंक आने वाली है। उसके बाद किसानों को यूरिया खवासा में मिल पाएगा।

पुलिस व एक भाजपा नेता ने खवासा व भामल से निकली कावड़ यात्रा में द्वेषभाव फैलाने का कूटनीति पूर्ण किया कार्य

पुलिस की कार्रवाई के चलते खवासा की कावड यात्रा बिना डिजे के खवासा में निकली।

भामल की यह कावड यात्रा मय डिजे की धुन के साथ ग्राम में होकर खवासा पुलिस चौकी के सामने से निकली , जिसके बाद पुलिस का विरोध सोशल मीडिया पर भी दिखा।

भाजपा नेता ने अपना पद नाम टीशर्ट पर लिखवाया जिसका जमकर हुआ विरोध।

माही की गूंज, खवासा।

श्रावण मास शिव भक्ति का एक प्रतीक होता है। श्रावण के इस पूरे महीने में भक्त अपने-अपने अनुसार कई तरह के अनुष्ठान करते हैं व शिव भक्ति में लीन रहते हैं। वहीं श्रावण मास के दौरान आने वाले सोमवार पर विशेष अनुष्ठान भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। जिसमें से एक है कावड़ यात्रा जो की प्राचीन काल से यह यात्रा चली आ रही है। कावड़ यात्रा में किसी प्रसिद्ध नदी,कूप या हेडपंप से भक्तगण एक समूह के साथ जल भरते हैं और एक निर्धारित दूरी तय कर अलग-अलग स्थान पर शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं। उक्त जल को गंगाजल के रूप में पवित्र जल माना जाता है। उक्त जल को शिवलिंग पर चढ़ाने के साथ भक्तगण शिव का जलाभिषेक करते हैं तथा उक्त कावड़ यात्रा शिव को समर्पित रहती है।

माना जाता है कि, कावड़ यात्रा से भक्तों के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उक्त कावड़ यात्रा एक समूह के साथ निकलती है जिसमें न ऊँच- नीच होती है न कोई भेदभाव होता है न कोई द्वेषभाव होता है और ना कोई तेरा या मेरा होता है। और उक्त कावड़ यात्रा राजनीति से भी परे होकर अपने आप में सबसे बड़ा यह कावड़ यात्रा एक भाईचारे एवं एकता का संदेश देती है। तथा यह भाईचारा ही मानसिक शांति व सुकून भी प्रदान करती है। क्योंकि वे एक मन-विचार के साथ भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति में लीन होते हैं। कावड़ यात्रा में विशेष रूप से प्रत्येक प्रकार की पवित्रता का ध्यान रखना होता है तथा यात्रा के दौरान बनाए गए नियमों का भी पालन करना पड़ता है। कहा जाता है कि, जो व्यक्ति इस यात्रा के दौरान अपने नकारात्मक विचारों से बचता है उसे पर भगवान शिव अवश्य रूप से प्रसन्न होते हैं।

खवासा व क्षेत्र की बात करें तो बताया जाता है कि, यहां भी श्रावण मास के दौरान वर्षों से कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। जिसमें समय अनुसार आयोजन समितियां जरूर बदलती रही होगी लेकिन भगवान शिव के प्रति भक्ति की भावना सिर्फ और सिर्फ समर्पण की ही रही है।

भाजपा नेता व पुलिस की मनमानी से कांवड़ियों में आक्रोश बना चर्चा का विषय

श्रावण मास के दूसरे सोमवार 21 जुलाई को खवासा ग्राम के कावड़ियों ने कावड़ यात्रा निकाली। उक्त कावड़ यात्रा का नाम शिव भक्ति कावड़ यात्रा दिया। सोमवार को 800 से 1000 भक्तगण उक्त कावड़ यात्रा में शामिल हुए। जिसमें महिला,पुरुष व कावड़ तोकने योग्य बच्चे भी थे। उक्त कावड़ियों वाहन से भेरूगढ़ माही तट पर पहुंचे और माही नदी का पवित्र जल भर करीब 15 किलोमीटर पैदल यात्रा कर कावड़िये डीजे की सामान्य ध्वनि पर बम-बम भोले के नारों के साथ नाचते- कूदते आ रहे थे। वही कावड़ियों के अनुसार उक्त धार्मिकमय कावड़ यात्रा में खवासा पुलिस ने आकर खलल पैदा करते हुए मकोडिया में ही डीजे को भगाने का प्रयास किया। कावड़िये भक्तों एवं समिति सदस्यों ने खवासा पुलिस से अनुरोध करते हुए कहा कि, डीजे की कर्कश ध्वनि नहीं है सामान्य ध्वनि के साथ ही हमारी यात्रा निकल रही है, आप कहो तो हम और ध्वनि को कम करवा देते हैं। उसी बहस के साथ उक्त कावड़ यात्रा धीरे-धीरे रोग्या देवी मंदिर के पास धीमे आवाज से बज रहे डीजे के साथ पहुंची। वहीं खवासा पुलिस ने सख्त लहजे में कावड़ियों को कह दिया कि, डीजे की आवाज कितनी भी धीमी हो पर खवासा ग्राम में डीजे की धुन के साथ यह कावड़ यात्रा नहीं निकलेगी खवासा पुलिस की यह नकारात्मकता क्यों रही यह तो पुलिस ही जाने...? पर थक हारकर कावड़िये मन मसोक कर रह गए। क्योंकि कावड़िये पुलिस की कूटनीतिक विचारों के चलते किसी प्रकार विवाद नहीं चाहते थे और निर्णय लिया कि, बिना डीजे से ही बिना नाचते हुए ग्राम में यात्रा निकालकर खवासा शिव मंदिर पर जल अभिषेक करेंगे और वही कावड़ियों ने किया। लेकिन पुलिस ने ऐसा व्यवहार खवासा के कावड़ियों के साथ क्यों किया यह कांवड़ियों के लिए भी अनसुलझा था। लेकिन यह अनसुलझा विचार दूसरे दिन पुलिस के विरोध में आक्रोश रूपी चर्चाओं के साथ सामने आया।

हुआ यह की, महाकाल मित्र मंडल भामल द्वारा एक कावड़ यात्रा मंगलवार 22 जुलाई को निकली जो 26 जुलाई तक उज्जैन पहुंचेगी। उक्त कावड़ यात्रा भामल से डीजे की धुन के साथ निकली और खवासा ग्राम में भी डीजे की धुन के साथ खवासा चौकी के सामने होकर उक्त धार्मिक भक्तिमय कावड़ यात्रा डीजे की धुन के साथ बामनिया होते हुए उज्जैन के लिए निकली। बात यह है कि, 21 जुलाई को खवासा की कावड़ यात्रा जो भेरूगढ़ से खवासा शंकर मंदिर पर पहुंची जिसमें खवासा पुलिस ने धीमी ध्वनि के साथ भी ग्राम में डीजे नहीं जाने दिया। वहीं एक दिन बाद ही 22 जुलाई को भामल से उज्जैन के लिए निकली कावड़ यात्रा जो की डीजे की धुन के साथ ही न केवल ग्राम में होकर निकली बल्कि खवासा पुलिस चौकी के सामने से होकर डीजे के साथ उक्त कावड़ यात्रा निकली ,लेकिन पुलिस ने डीजे को नहीं रोका नहीं बंद करवाया! ऐसे में पुलिस ने अपनी नकारात्मकता की सोच के साथ आपस में स्थानीय स्तर पर क्षेत्र में द्वेषभाव फैलाने का कृत्य किया जिसकी निंदा की जा रही है। वहीं खवासा शिव शक्ति कावड़ यात्रा समिति सदस्यों एवं कावड़ियों का कहना है कि, कावड़ यात्रा चाहे खवासा से निकली हो, चाहे भामल से निकली हो, चाहे कहीं और से कावड़ यात्रा निकलती हैं वह हम सब की हमारी ही कावड़ यात्रा है। ऐसे में हमारा किसी कावड़ यात्रा का विरोध नहीं है। परंतु खवासा पुलिस की दोहरी कूटनीति जिसमें एक कावड़ यात्रा में डीजे को ग्राम में नहीं जाने दिया तो वहीं दूसरे दिन निकली कावड़ यात्रा जो डीजे की धुन के साथ पुलिस चौकी के सामने से निकली लेकिन पुलिस ने डीजे को नहीं रोका? जिससे साफ प्रतीत होता है कि, पुलिस ने कूटनीति के साथ घिनौना कृत्य कर आपसी में हमारे भाईचारे में द्वेषभाव बढ़ाने के लिए उक्त घिनौना कृत्य किया है। और कहीं न कहीं पुलिस ही चाहती है कि, कावड़ यात्रा के नाम पर हमारे शांत क्षेत्र में अशांति फैले लेकिन हम पुलिस के उक्त घिनौने कृत्य को समझ चुके हैं। और पुलिस को इसका जवाब आज नही तो कल देना ही पड़ेगा कि, पुलिस ने दौहरा यह कृत्य क्यों किया...?

वहीं दूसरी और खवासा भाजपा मंडल के महामंत्री रामसिंह पालरा ने अपनी नकारात्मक सोच का परिचय देकर भामल से निकली कावड़ यात्रा में आपसी भाईचारे में सेंध लगाने का कूटनीतिक कृत्य किया है। हम पहले ही बता चुके हैं कि, कावड़ यात्रा ऊँच- नीच जातिवाद व किसी भी राजनीतिक पार्टी से परे होकर यह कावड़ यात्रा निकलती हैं। यानीकि उक्त यात्रा में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी की विचारधारा के व्यक्ति व नेता या फिर कर्मचारी भी इस यात्रा का लाभ लेते हैं। लेकिन भाजपा के नेता व मंडल महामंत्री उक्त महाशय ने कावड़ियों के लिए टीशर्ट बनवाए जिसमें इस भाजपा के महाशय ने उक्त टीशर्ट के पीछे अपने नाम के साथ अपने पद का उपयोग मंडल महामंत्री भाजपा लिखा। जैसे ही कावड़ियों में सम्मिलित भक्तों के पास यह टीशर्ट पहुंचे और मंडल महामंत्री भाजपा टीशर्ट पर लिखा देखा तो यात्रा में सम्मिलित कर्मचारियों ने यह टीशर्ट लेने से मना कर दिया। वहीं अन्य पार्टी के विचारधारा रखने वाले ने भी इस पर आपत्ति जताई। वहीं यात्रा निकलने के पूर्व ही भाजपा नेता रामसिंह पालरा की वजह से एक अनचाहा आपसी में विवाद का मुद्दा बन गया। तो ऐसे में रामसिंह पालरा द्वारा अपनी पार्टी के साथ अपने नाम को चमकाने के लिए टीशर्ट पर लिखा पार्टी एवं पदनाम का विरोध ऐसा हुआ कि, कुछ भक्त युक्त कावड़ यात्रा में गए ही नहीं और पानी के लोटे और कावड़ की लकड़ी रामसिंह पालरा को थमाकर अपने घर चले गए।

हे शिव भाजपा नेता व पुलिस की नकारात्मकता पर करना दया

श्रावण मास एक पवित्र विचारों के साथ शिव भक्ति में लीन होने का यह महिना है। ऐसे में हम भी हमारी क्षणिक भक्ति के साथ किसी के साथ गलत हो यह विचार हम हमारे मन मस्तिष्क में नहीं ला सकते हैं। भले ही सामने वाले व्यक्तियों ने अपनी नकारात्मक विचारों के साथ कूटनीतिक पूर्ण कार्य कर द्वेषभाव फैलाकर भाईचारे में सेंध लगाने का घिनौना कार्य किया है। ऐसे में भी हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि, वे सब पर दया बनाए रखें और पुलिस व रामसिंह पालरा की इस गलती को क्षमा कर सही मार्ग प्रसस्थ करे।

बच्चों की सहूलियत के लिए बनाई गई स्कूलों में यूनिट में ना तो नल लगे ना पाइपलाइन

इस तरह से योजना ध्वस्त।

माही की गूंज, खवासा।

शासकीय स्कूलों में दर्ज बच्चों के लिए जल जीवन-जल मिशन के अंतर्गत शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने वाली योजना फेल ही साबित हो रही है। करोडो रुपये राशि खर्च करके यूनिट लगाई गई लेकिन बच्चो को एक बूंद पानी इस योजना के तहत नही मिला। ऐसे में बच्चों को घर से पीने का पानी लेकर आना पड़ रहा है। पीएचई द्वारा ठेकेदार के माध्यम से शासकीय स्कूलों में हैंडपंप लगाकर हजारों रुपये खर्च करके सिंगल फेस मोटर, पाइपलाइन और वॉटर टैंक लगाकर पेयजल यूनिट तैयार की गई। इसके बावजूद बच्चों को पानी नहीं मिल पा रहा है। यूनिट लगाने का उद्देश्य था कि, बच्चों को शुद्ध पेयजल के लिए भटकना ना पड़े और हाथ धोने के साथ शुद्ध जल उपलब्ध हो सके। यहां यूनिट निर्माण में ठेकेदारों की मनमानी व विभागीय लापरवाही के कारण कई गांव में यह योजना घटिया निर्माण की भेट चढ़ गई। कई जगह यह यूनिट अधूरी पड़ी हुई तो कई जगह तो टूट गई है, लेकिन इस और जिम्मेदारों का कोई ध्यान ही नहीं।

हैंड वॉश यूनिट कई जगह हो गए खराब तो कई जगह होने लगे ध्वस्त

भामल संकुल के अंतर्गत कई जगह हैंड वॉश यूनिट अधूरी पड़ी हुई तो कई जगह टूट गई है। ठेकेदार ने खाना पूर्ति के लिए गांव में मात्र ढांचा तैयार करके छोड़ दिया। सिर्फ जिओ टेकिंग करके लोकेशन के आधार पर ठेकेदारों व अधिकारियों की बल्ले-बल्ले हुई। ग्रामीण अंचलों की स्कूलों में बच्चों को आज भी शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है।

घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गई हैंडवॉश यूनिट योजना

माही की गूंज को मिली जानकारी के अनुसार कुछ ऐसा ही मामला भामल हाई स्कूल के साथ ही माध्यमिक विद्यालय भामल, प्राथमिक विद्यायल वडलीपाड़ा, माध्यमिक विद्यालय नरसिंगपाड़ा। कुकड़ीपाड़ा संकुल के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय रन्नी, नौगांवा नगला आदि स्कूलो मे हैंडवाश यूनिट बन तों गईं लेकिन उसके नलों में पानी कभी नहीं आया। धरातल पर हैंड वॉश यूनिट टूट-फुट चुकी है बच्चों को पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। एक तरफ प्रदेश सरकार नई योजनाएं धरातल पर मूर्त रूप देने का दावा करती है लेकिन इन योजनाओं में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होने के कारण योजना धरातल पर दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर भी प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई के नाम पर लीपा-पोती करते हैं। और मामले को रफा-दफा कर दिया जाता है। तो वही ठेकेदारों से सेटिंग करके अधिकारीयों की बल्ले-बल्ले होते हुए भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं।

श्रृंगेश्वर धाम पर सावन के पवित्र महीने में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब

माही की गूंज, झकनावदा/रायपुरिया।

सावन के पवित्र महीने में भोले के भक्तों द्वारा बोल बम ,बोल बम ,हर हर महादेव,भोले शंभु भोलेनाथ जैसे नारों के साथ भक्ति में लीन अपने कंधों पर कावड़ उठाए हर्षोल्लास के साथ कावड़ में जल भर कर पैदल चल कर बाबा महाकाल को जलाभिषेक करने के लिए ग्राम बनी, बोलसा, सेमरोड, धतुरिया और धार जिले के भानगढ़ से काल भैरव डाक तूफानी कावड़ यात्रा का समाजसेवियों ओर सामाजिक संगठन द्वारा स्वागत कर स्वल्पाहार कराकर दूर दराज से आए सभी कावड़ियों का अभिनन्दन किया गया। इस आयोजन में मुख्य रूप से हेमेंद्र कुमार जोशी,भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र राठौड़,श्रेणिक कुमार कोठारी, समाजसेवी गोपाल राठौड़, सुरेश राठौड़,फकीरचंद माली,ठाकुर परीक्षितसिंह राठौर, पूर्व सांसद प्रतिनिधि राजेश कॉसवा,विकास जोशी, नारायण प्रजापत,राजेंद्र मिस्त्री,डॉक्टर अपूर्वा मजमुदार,दामोदर पडियार, जीवन वैरागी,कमल चोयल,पंकज राठौड़ आदि ने अपना सहयोग प्रदान किया।

नवागत मेडिकल ऑफिसर का किया स्वागत

माही की गूंज ,करवड़।

पेटलावद विकासखंड के अंतर्गत आने वाला करवड़ ग्राम में लंबे समय से ग्रामवासियों के द्वारा डाक्टर की मांग की जा रही थी। जिसको देखते हुए कैबिनेट मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल ऑफिसर दीक्षा पटेल की पद स्थापना की गई। मेडिकल ऑफिसर का स्वागत सरपंच विकास बाबूलाल गामड़, सचिव राजेंद्र रेड्डी एवं मेडिकल स्टाफ लता सोलंकी के द्वारा पुष्पगुच्छ देकर पंचायत भवन पर स्वागत किया गया। वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ विमला सिंगाड़ के द्वारा सेवाएं दी जा रही है, नए मेडिकल ऑफिसर के रूप में दीक्षा पटेल ने पदभार ग्रहण किया। कैबिनेट मंत्री सुश्री भूरिया को ग्रामीणों के द्वारा धन्यवाद दिया गया। समय पर महिलाओं को डिलीवरी एवं प्राथमिक उपचार के लिए अब अन्य स्थानों पर भटकना नहीं पड़ेगा । सरपंच विकास बाबूलाल गामड़ ने भी कैबिनेट मंत्री को धन्यवाद दिया और बताया कि, लंबे समय से हमारे द्वारा मेडिकल ऑफिसर की मांग की जा रही थी जिसको देखते हुए कैबिनेट मंत्री सुश्री भूरिया ने महिला डॉक्टर की पदस्थी की ग्रामीणों में खुशी का माहौल है।

ग्राम पंचायत की उदासीनता नाले की निकाली नही होने से एक ही जगह हो रहा जल जमाव

माही की गूंज, भामल।

ग्राम पंचायत भामल में 21 जून को जब उल्टी दस्त से कई ग्रामीण बीमार हुए तो स्थानीय प्रशासन ने तत्काल ग्राम भामल में राहत कैंप लगाने के साथ जो लोग बीमार हुए उनका प्राथमिक इलाज भी किया गया। उसके बाद जनपद के अधिकारी व पंचायत ने मिलकर सभी जगह नालों की साफ-सफाई व गांव में जहां भी गंदगी थी सभी जगह पर साफ-सफाई की गईं। जहां पानी निकासी के लिए नाला नहीं था वहां जेसीबी के माध्यम से नाला निकाला गया। जिन लोगों ने बाजना मार्ग रोड के आसपास जहां नाली मे पानी निकासी नहीं हो रहा था तथा यहा अतिक्रमण कर रखा था उनके अतिक्रमण को भी जेसीबी के माध्यम से जनपद के अधिकारियों ने हटवाया था। लेकिन एक जगह पानी जाने के लिए निकासी नही हो रही थी तों वहा जेसीबी से नाला बनाया गया। नाला बनने के बाद वहां आम आदमी के जाने के लिए रास्ता जाम हो गया और वहा गड्ढे का रूप ले लिया।

जानकारीनुसार ग्राम पंचायत भामल के सामने भारत खेर के मकान के पास सोलंकी मोहल्ले का पूरा नाले का पानी जिसमें बारिश का पानी निकलता है। उसी नाले का पूरा पानी एक ही जगह संग्रहित हो रहा है तथा फिर से बीमारी फैलने का डर ग्रामीणों को सता रहा है। वही एक जगह गड्ढा होने से तालाब जैसा दिखाई दे रहा है। इस रास्ते का आसपास के ग्रामीण आने-जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं अब गड्ढे से होकर उनको निकालना पड़ता है। वही नजदीकी एक प्राइवेट स्कूल भी संचालित होती है। बच्चे भी गांव के इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं जिनको निकलने में परेशानियों से गुजरना पड़ता है। बताते हैं यह नाला सरकारी है और इसके आसपास जिनकी निजी जमीन है उन्होंने नाले के आसपास अतिक्रमण कर रखा है जिसकी वजह से नाला सिकुड़ता गया है और जगह कम बची है।

नाले को बनाने के लिए पुलिया भी स्वीकृत हुआ है और इसकी राशि भी ग्राम पंचायत में स्वीकृत हुई है लेकिन अतिक्रमण की वजह से ग्राम पंचायत यहां नाले की निकासी वह पुलिया नहीं बनवा पा रही है। वही ग्राम पंचायत भी अतिक्रमण हटाने की कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है।

लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि, यहां पर नाला निकासी के साथ ही पानी की निकासी होनी चाहिए। साथ ही जिन्होंने सार्वजनिक नाले के आसपास अतिक्रमण कर लिया उनसे सीमांकन करके अतिक्रमण मुक्त करना चाहिए यह मांग की है। ग्रामीण यह भी कह रहे है कि, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। तो दुसरी और ग्राम पंचायत भामल इसका मखोला उड़ा रही है इसकी बानगी देखना हो तो आप पंचायत के नजदीक जमा नाले को देख सकते है।

संपादकीय

अविश्वास की रिकॉर्डिंग

संक्रमणकाल से गुजर रहे भारतीय समाज में पति-पत्नी के दरकते रिश्ते समाजविज्ञानियों के लिए चिंता का विषय हैं। आये दिन विभिन्न अदालतों में ऐसे मामलों से जुड़े विवाद मीडिया की सुर्खियां बनते रहते हैं। नि:संदेह, भारतीय समाज में पहले ऐसे मामले कम ही नजर आते थे और विवाह को सात जन्मों का बंधन कहा जाता रहा है। यहां तक कि हिंदू विमर्श में तलाक शब्द का कोई सटीक पर्यायवाची भी नहीं मिलता। लेकिन इधर रिश्तों में लगातार बढ़ता अविश्वास, अलगाव व विवाद वर्तमान समय की हकीकत है। बल्कि पिछले दिनों एक न्यायाधीश को यहां तक कहना पड़ा कि वैवाहिक विवादों के बोझ से न्यायिक प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा है। इसी क्रम में पिछले दिनों पति-पत्नी के विवाद में गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई फोन कॉल को साक्ष्य मानने की बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादो से जुड़े एक अहम फैसले में कहा है कि पति या पत्नी द्वारा गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत अब एक सबूत के तौर पर स्वीकार होगी। शीर्ष अदालत का कहना था कि इस तरह की रिकॉर्डिंग फैमिली कोर्ट में एक अहम सबूत के तौर पर स्वीकार की जा सकती है। दरअसल, इस बाबत पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को ही रद्द कर दिया। दरअसल, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का इस बाबत मानना था कि किसी पक्ष की जानकारी के बिना उसकी बातचीत को रिकॉर्ड करना उसकी निजता का उल्लंघन होगा। उच्च न्यायालय का तर्क था कि इस रिकॉर्डिंग को फैमिली कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय का कहना था कि आमतौर पर पति-पत्नी सामान्य तौर पर या आवेश में खुलकर बात करते हैं। उन्हें इस बात का भान नहीं होता कि कहीं उनकी बात रिकॉर्ड हो रही है या उनकी बातचीत भविष्य में अदालत में साक्ष्य की तौर पर पेश की जा सकती है।

अपने तर्क के समर्थन में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने कुछ न्यायिक फैसलों का भी जिक्र किया था। खासकर आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के एक फैसले का उल्लेख किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पति-पत्नी की सहमति के बिना बातचीत को रिकॉर्ड करना निजता का उल्लंघन है। साथ ही गैर-कानूनी भी है। इस तरह के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने उन दलीलों को अस्वीकार्य किया कि जिसमें कहा गया था कि इस तरह के साक्ष्य की अनुमति देने से घरेलू सौहार्द व वैवाहिक रिश्तों पर आंच आएगी। यह भी कि इससे समाज में पति-पत्नी की जासूसी की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साक्ष्य अधिनियम का भी अतिक्रमण होगा। शीर्ष अदालत की पीठ का इस बाबत कहना था कि अदालत में पहुंचे रिश्ते इस बात का पर्याय हैं कि दोनों के रिश्ते सहज व सामान्य नहीं हैं। जाहिरा तौर पर रिश्तों में अविश्वास के चलते ही वैवाहिक मामले कोर्ट तक पहुंचते हैं। उल्लेखनीय है कि बठिंडा की एक परिवार अदालत ने पत्नी की क्रूरता साबित करने वाली फोन रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के तौर पर प्रयोग करने की अनुमति दी थी। जिसे पत्नी ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी। उसकी दलील थी कि यह रिकॉर्डिंग उसके संज्ञान में लाए बिना की गई थी। जिससे उसके निजता के मूल अधिकार का हनन होता है। जिस पर उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार किया, साथ ही फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि बातचीत एक पक्ष ने गोपनीय ढंग से रिकॉर्ड की है, अत: इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह भी कहा कि तय करना कठिन है कि ये बातचीत किन परिस्थितियों व भावनात्मक आवेश के चलते हुई थी। ऐसे में आरोपों की तार्किकता सिद्ध करना कठिन है। साथ ही बहुत संभव है कि रिकॉर्ड करने वाले पक्ष ने सतर्क होकर प्रतिक्रिया दी हो। ऐसे में उसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक नहीं हो सकती।

दूरगामी रणनीति से बनेंगे पड़ोसियों से अच्छे संबंध

पुष्परंजन

किसी ने सोचा नहीं था, मोदी और मुइज़्ज़ू कभी 'सेम पेज' पर आ पाएंगे। यों, पीएम मोदी मालदीव तीसरी बार जा रहे हैं। मगर, राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के शासन के दौरान उनकी यह पहली यात्रा होगी। उनकी इस यात्रा से माले और नई दिल्ली के बीच संबंधों की नई इबारत लिखी जाएगी। विश्लेषकों ने इसे चीन के प्रभाव को 'पछाड़ने और उससे आगे निकलने' का प्रयास बताया है। 2025 के भारतीय बजट में, मालदीव को 6 अरब रुपये के आवंटन के बाद माले का भरोसा दिल्ली पर बढ़ा, जो पिछले वर्ष के 4.7 अरब रुपये से अधिक थी। इसे दक्षिण एशियाई लाभार्थियों में सबसे बड़ी वृद्धि बताया गया था। मोदी की मालदीव यात्रा पर केवल चीन-पाकिस्तान नहीं, अमेरिका की भी नज़र है।

1 जनवरी, 2025 को चीन-मालदीव मुक्त व्यापार समझौता (सीएमएफटीए) लागू हो गया, जिस पर 2014 में हस्ताक्षर हुए थे। मालदीव की संसद ने 2017 में इस व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इब्राहिम सोलिह के नेतृत्व वाली सरकार ने 2018 में इसे निलंबित कर दिया था। पिछले साल जनवरी में, मालदीव और चीन ने पर्यटन सहयोग समझौते सहित 20 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए और एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। मुइज़्ज़ू प्रशासन ने चीन से लिए गए 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के ऋणों के पुनर्गठन की भी मांग की।

मालदीव ने पिछले साल चीनी अनुसंधान पोत जियांग यांग होंग-3 को अपने जलक्षेत्र में आने की अनुमति दी थी, जिससे भारत में चिंताएं बढ़ गई थीं। जनवरी, 2025 में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने मालदीव का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू से बातचीत की, और द्विपक्षीय संबंधों को दुरुस्त करने पर ज़ोर दिया। वांग यी को लग रहा था कि भारत-चीन फिर से नज़दीक आ रहे हैं।

यों, जनवरी, 2024 में ही संकेत मिल गया था कि मुइज़्ज़ू भारत से संतुलित सम्बन्ध बनाने को इच्छुक हैं। मुइज़्ज़ू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए तीन मंत्रियों मरियम शिउना, मालशा शरीफ, और महजूम मजीद को निलंबित कर दिया था। 6 से 10 अक्तूबर, 2024 के दौरान मुइज़्ज़ू भारत आये और दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की, जहां दोनों ने एक संयुक्त विज़न दस्तावेज़ जारी किया था। उस अवसर पर हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग को गहरा करने की योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। समझौते में कहा गया था कि भारत मालदीव के रक्षा बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने में मदद करेगा, जिसमें भारत की मदद से निर्मित माले में अत्याधुनिक रक्षा मंत्रालय के भवन का उद्घाटन भी शामिल है।

ऐसा लगता है, मुइज़्ज़ू अपने चीन समर्थक होने का मुलम्मा उतारना चाहते हैं। दो साल से उन्हें 'प्रो चाइना प्रेसिडेंट' ब्रांडेड किया गया था। नवंबर, 2023 में भारत-मालद्वीव उभयपक्षीय संबंध सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए, जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू, जिन्होंने 'इंडिया आउट' का प्रचार किया था। उन्होंने

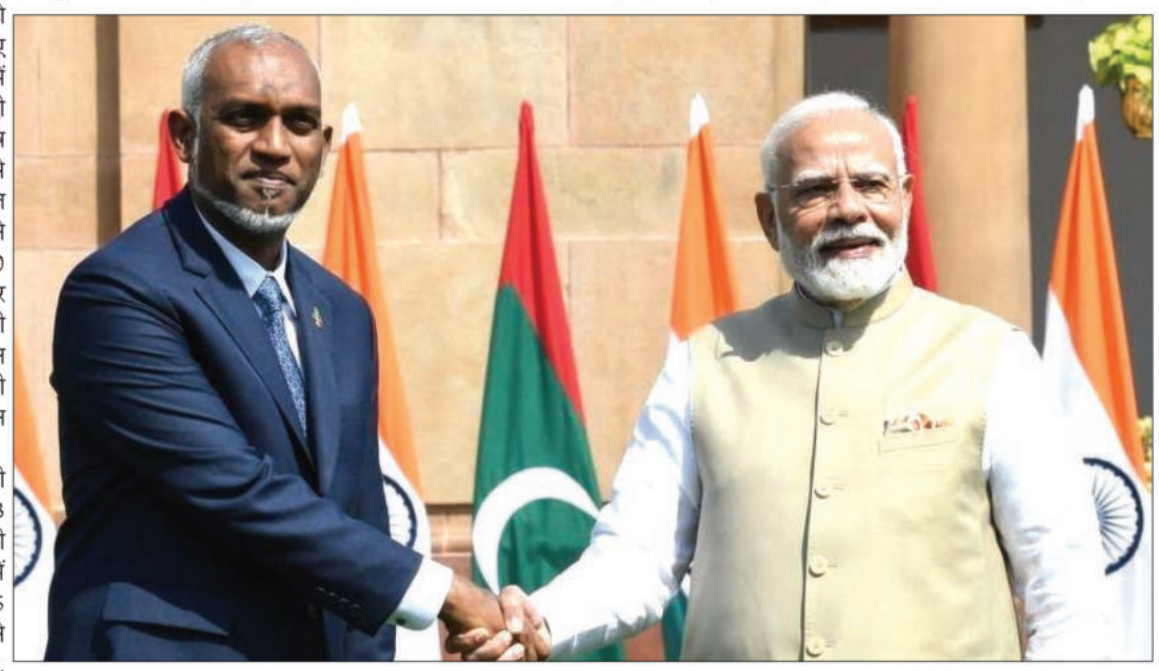

राष्ट्रीय संप्रभुता की चिंताओं का हवाला देते हुए नई दिल्ली को भारत द्वारा उपहार में दिए गए दो हेलीकॉप्टरों और एक फिक्स्ड-विंग विमान का संचालन और रखरखाव करने वाले 89 सैनिकों को वापस बुलाने का आदेश दिया था। इससे पाकिस्तान और चीन दोनों प्रसन्न थे।मालदीव-पाकिस्तान के संबंधों को समझना है तो वहां की संसद को देखिये, जिसका निर्माण पाकिस्तान ने 45 मिलियन रुपये लगाकर किया था। माले के मागू स्थित संसद भवन 'मज़लिस' का उद्घाटन 1 अगस्त, 1998 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की उपस्थिति में किया गया था। उसके 19 साल बाद, 25 जून, 2017 को मालदीव के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी पत्नी कलसूम नवाज शरीफ को आमंत्रित किया था। नवाज़ को दोबारा मालदीव बुलाने से पहले तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन 7 मई, 2015 को इस्लामाबाद भी गये थे। पाक सेना के तत्कालीन प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने मार्च, 2018 के अंत में मालदीव का दौरा किया था। इस समय पाकिस्तान में मालदीव के अधिकांश छात्र देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं। 550 से 600 मालदीवियन युवा अपंजीकृत तालिब मदरसों में दीक्षा ले रहे हैं।

वर्ष 1965 में मालदीव एक स्वतंत्र देश बना। भारत, इस द्वीपीय राष्ट्र को मान्यता देने वाला पहला देश था। वर्ष 1972 में भारत ने मालदीव में अपना पहला उच्चायोग स्थापित किया, जबकि 2004 में मालदीव ने नई दिल्ली में अपना पहला पूर्ण राजनयिक मिशन खोला था। ठीक से देखा जाए, तो मोदी के कालखंड में मालदीव से उतार-चढ़ाव वाले संबंध रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चीन पर दोष मढ़ने की बजाय, भारत को अपने पड़ोसी देशों में चल रही गतिविधियों को ध्यान में रखकर दूरगामी रणनीति बनाने की ज़रूरत थी। आप मानें न मानें, पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब और तुर्की का नेक्सस की भूमिका दिल्ली से माले के संबंध बिगाड़ने में दरपेश रही है।

रविवार को अपने बयान में, राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के कार्यालय ने यह नहीं कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। बल्कि, बयान में यह उद्धृत था कि 26 जुलाई को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस और मालदीव-भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी कई संयुक्त परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

ऐसा क्या है, कि मालदीव से हमारी कनेक्टिविटी कम हो जाती है? 'पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट', भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा है, लेकिन हम भाषाई और सांस्कृतिक रूप से सही से जुड़ नहीं पाए हैं। मालदीव किसी ज़माने में हिन्दू और बौद्ध देश माना जाता था। इसके अंतिम सम्राट, राजा धोवेमी ने वर्ष 1153 में इस्लाम धर्म अपना लिया; और अपना नामांतरण कर इस्लामिक नाम सुल्तान मुहम्मद अल-आदिल रख लिया।

धिवेही वहां की आधिकारिक भाषा है। पाकिस्तान सरकार ने 25 जुलाई, 2024 को 'धिवेही बहुगे अकादमी' को 10,000 अमेरिकी डॉलर का दान दिया। धिवेही भाषा अकादमी का प्रतिनिधिमंडल अनुवाद, संगोष्ठियों के बाइ'स पाकिस्तान जाता रहा है। उर्दू और धिवेही के बीच सहयोग, डिजिटाइज़ की संभावनाओं को ये मिलकर आगे बढ़ा रहे सवाल हैं, भारत इस दिशा में पीछे क्यों रह गया? इश्धू लोमाफ़ानु मालदीव में अब तक खोजी गई सबसे पुरानी ताम्रपत्र पुस्तक है। यह पुस्तक 1194 ईस्वी में बौद्ध राजा श्रीगगनआदित्य के शासनकाल में लिखी गई थी। आधुनिक युग में हुसैन सलाउद्दीन ने 'सियारथुन्नबविया' लिखा। कवि अद्दू बंदेयरी हसन मानिकुफ़ान, मालदीव भाषा के सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख साहित्यकार हैं, जिन्होंने 'धियोगे रायवरु' लिखा। अन्य रचनाकारों में बोडुफेनवालहुगे सिदी, मरियम सईद, अमीना फ़ैज़ा, इब्राहिम शिहाब, अब्दुल रशीद हुसैन की रचनाओं के भारतीय अदबी संसार कितना ज्ञात है? यह सवाल उठाना तो बनता है।

राष्ट्रहित में नही भाषाई अस्मिता की जंग

विश्वनाथ सचदेव

पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले एडवोकेट उज्ज्वल निकम को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। निकम के अनुसार यह सूचना उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने टेलीफोन पर संपर्क करके दी थी। प्रधानमंत्री ने फोन पर एडवोकेट निकम से कहा था, 'मी मराठी बोलूं का हिंदी?' इस पर निकम कुछ हंस दिये, पर प्रधानमंत्री ठहाका लगाकर हंसे थे। वैसे प्रधानमंत्री का मराठी में बोलना और निकम एवं मोदी जी का हंसना स्वाभाविक-सी बात है, पर हाल के दिनों में महाराष्ट्र में भाषा की जो राजनीति चल रही है उसे देखते हुए यह प्रकरण सामान्य से थोड़ा हटकर लग रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा निकम के साथ मराठी में बोलने वाली यह बात जिस दिन अखबार में छपी, उस दिन एक अन्य समाचार भी अखबार के पहले पृष्ठ पर छपा था। यह समाचार मुंबई के उपनगर विरार का था, जहां उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक रिक्शा वाले की इसलिए पिटाई कर दी कि वह मराठी में नहीं बोल पा रहा थाद्द हिंदी में बोल रहा था। रिक्शा चालक उत्तर प्रदेश का था और शिवसेना के कार्यकर्ताओं का मानना था कि उसे अपनी कर्मभूमि की भाषा मराठी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र में मराठी न बोल पाना मराठी भाषा का अपमान कैसे हो गया, पता नहीं, पर प्रधानमंत्री द्वारा एडवोकेट निकम से मराठी में बोलना यह संकेत तो दे ही रहा है कि राज्य में भाषा को लेकर फिर से उठा यह विवाद अप्रिय स्थितियां उत्पन्न कर रहा है।

महाराष्ट्र में आकर जीविका कमाने वाले को राज्य की भाषा आनी चाहिए, इस बात से किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सच बात तो यह है कि एक से अधिक भारतीय भाषाएं जानने वाले भारतीय को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि वह बहुभाषी है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र नहीं है, भाषा हमारी अस्मिता है, पहचान है। हमारे संविधान में हिंदी को देश की राजभाषा का स्थान दिया गया है, लेकिन संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित की गयी सभी बाईस भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं। सब पर हमें गर्व है। इनमें से किसी एक का भी अपमान समूची भारतीयता का अपमान है। अर्थात? स्वयं अपना अपमान। कोई क्यों करना चाहेगा भला अपना अपमान? सच तो यह है कि अपनी भाषाई विविधता पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। भाग्यशाली हैं हम कि हमारे पास भाषाओं का इतना बड़ा खज़ाना है।

हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि यह अहसास हम सब में जगे। लेकिन यह भी एक पीड़ादायक सच्चाई है कि अक्सर भाषा को राजनीति का हथियार बनाया जाता है। महाराष्ट्र में इन दिनों चल रहे भाषाई-विवाद के पीछे भी कुछ ऐसी ही राजनीति है। कुछ अरसा पहले महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा-नीति में परिवर्तन संबंधी शासनादेश जारी किया था, जिसमें यह व्यवस्था की गयी थी कि प्राथमिक कक्षाओं में तीन भाषाएं पढ़ाई जाएंद्द मातृभाषा यानी मराठी, अंग्रेजी और हिंदी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) को यह राजनीतिक स्वार्थ साधने का अवसर दिखा। उसने इसे हिंदी-मराठी का विवाद बना दिया और तरीका वही अपनाया जो बीस साल पहले आजमाया जा चुका थाद्द यानी मराठी माणूस और मराठी अस्मिता की बात। साथ ही जोर-जबरदस्ती वाली नीति। उद्धव ठाकरे को भी इसमें अवसर दिख गया। मराठी के अपमान का नारा लगाकर राजनीति सधने लगी। राजनीतिक स्वार्थ का ही तकाज़ा था कि महाराष्ट्र सरकार को भी तीन भाषाओं वाला शासनादेश वापस लेना पड़ा। अब एक समिति बनाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। पर मुद्दे की आंच ठंडी नहीं हुई। उज्ज्वल निकम से प्रधानमंत्री का हल्के-फुल्के अंदाज में पूछा गया भाषा वाला सवाल और विरार में रिक्शा चालक की पिटाई वाला प्रकरण इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भाषाई-विवाद वाली राजनीति की आंच अभी सुलग रही है और इसे अभी और सुलगाया जायेगा। 'मनसे' और 'उबाठा' की कोशिश रहेगी कि मुंबई महानगरपालिका समेत राज्य में नगर निकायों के चुनाव तक यह आंच सुलगती रहे, ताकि उनकी राजनीति की रोटियां सिकती रहें। पहले भी समय-समय पर स्थानीय और पर प्रांतियों का मुद्दा राजनीति का हथियार बनता रहा है, अब भी बनेगा। इसका किसको कितना लाभ मिलेगा, यह तो भविष्य ही बतायेगा, पर भाषाई अस्मिता और प्रांतीयता के नाम पर लड़ी जा रही यह लड़ाई किसी भी दृष्टि से राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं कहीं जा सकती।

महाराष्ट्र की राजनीति में अपना स्थान खोजती 'मनसे' और अपना खोया स्थान फिर से प्राप्त करने की कोशिश में लगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को इस ताज़ा विवाद के सहारे जुड़ने का मौका भले ही मिल गया हो, पर राष्ट्रीय हितों को देखते हुए भाषाई अस्मिता के नाम पर लड़ी जा रही इस लड़ाई का समर्थन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि यह राजनीति और भाषा के नाम पर लड़ी जाने वाली लड़ाई सिर्फ महाराष्ट्र में ही हो रही है। देश के अन्य राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु, कर्नाटक, असम आदि में भी इस तरह की विभाजनकारी प्रवृत्तियां समय-समय पर सिर उठाती रही हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे राजनेता अपनी राजनीति को चमकाने की इस राष्ट्र-विरोधी प्रवृत्ति से उबरें।

यह राष्ट्र हम सब का है। हम यानी हम सब भारतीयों का। हमारा संविधान देश के हर नागरिक को देश में कहीं भी जाने-बसने का अधिकार देता है। भाषा, धर्म, जाति आदि के नाम पर देश के किसी भी नागरिक से उसके वे अधिकार छीनने की कोशिश स्वीकार्य नहीं हो सकती जो संविधान ने उसे दिये हैं।

यह सही है कि देश की सारी भाषाएं हम सब की हैं फिर भी क्षेत्र-विशेष की अपनी मातृ-भाषा के प्रति अनुराग और गर्व का भाव होना ग़लत नहीं कहा जा सकता। पर हमारी भाषाएं हमारे आंगन की दीवार नहीं हैं, पुल हैं हमारी भाषाएं जो हमें एक-दूसरे से जोड़ती हैं। यहीं इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि हिंदी को मात्र इसी आधार पर राजभाषा का दर्जा दिया गया था कि देश की बहुत बड़ी आबादी हिंदी बोलती-समझती है। जहां तक प्राचीनता और समृद्धि का सवाल है तमिल, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं हिंदी से कहीं अधिक समृद्ध हैं। अपनी सब भाषाओं के प्रति हम में आदर का भाव होना चाहिए। इसी आदर का यह भी तकाज़ा है कि हम किसी को इसलिए 'सज़ा' का पात्र न मान लें कि वह हमारी भाषा नहीं जानता। पिछले कुछ दिनों में मुंबई में भाषा के जानने, न जानने को लेकर जिस तरह मारपीट की घटनाएं हुई हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई किसी भाषा को नहीं जानता इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाना चाहिए कि वह उस भाषा का अपमान कर रहा है। किसी भाषा को न सीख पाने के भी कई कारण हो सकते हैं। कोशिश तो यह होनी चाहिए कि हम जितनी भाषाएं सीख सकें, सीखें। विनोबा भावे अनेक भाषाएं जानते थे, 46 वर्ष की आयु में उन्होंने अरबी और फारसी सीखी थी। जीवन के अंतिम दिनों में वह जापानी भाषा सीख रहे थे! मराठी उनकी मातृभाषा थी पर उन्होंने कभी किसी से अपेक्षा नहीं की कि वह उनकी भाषा में पारंगत हो। हां, वे स्वयं अवश्य कई भाषाओं में पारंगत हो गये थे।

बहरहाल, भाषा के नाम पर जिस तरह देश में द्वेष का वातावरण पनप रहा है, वह किसी भी विवेकशील नागरिक की चिंता का विषय होना चाहिए। किसी रिक्शा वाले को, किसी दुकानदार को, किसी सरकारी कर्मचारी को 'कान के नीचे बजाने' की भाषा में धमकी देना किसी भी दृष्टि से सही नहीं ठहराया जा सकता। भाषा की अपनी मर्यादा होती है उसका पालन होना ही चाहिए। भाषा के नाम पर की जाने वाली राजनीति को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, इस राजनीति की भर्त्सना ज़रूरी है। आज भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में जो कुछ रहा है, उसके औचित्य पर सवालिया निशान लगना ही चाहिए और उत्तर हर विवेकशील नागरिक को देना है।

भाजपा नेता की हत्या सुलझाने में पुलिस नाकाम

माही की गूंज, मंदसौर।

नाहरगढ़ के ग्राम हिंगोरिया बड़ा में भाजपा नेता श्यामलाल धाकड़ हत्याकांड में एक नया एंगल सोशल मीडिया पर चर्चाओं में रहा। अभी तक महिला मित्र को लेकर जांच का बिंदु चल रहा था।

परिजनों ने भी महिला मित्र को संदेही बताया, लेकिन इसी महिला मित्र को नाहरगढ़ टीआई प्रभात गौड़ पहले ही जानते थे। वारदात से पहले टीआई और संदिग्ध महिला भी कॉल पर लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। पलिस की सीडीआर मतलब कॉल डिटेल रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। मतलब साफ है कि टीआई भाजपा नेता की महिला मित्र को पहले ही पहचानते थे, लेकिन फिलहाल पुलिस की बात करें तो हत्यारे अभी पलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसके अलावा पुलिस अन्य एंगलों पर भी जांच कर रही है। मृतक श्यामलाल के पिता दौलतराम धाकड़ का आरोप है कि महिला सना खान के उनके बेटे से अवैध संबंध थे और उसी ने सुपारी देकर इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया है।

दौलतराम ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे और सडकों पर उतरेंगे। श्यामलाल की पुत्री मोनिका ने भी बताया कि घटना वाले दिन ही उन्होंने महिला सना के बारे में पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मोनिका का कहना है कि उनके पिता के साथ महिला के संबंध संदिग्ध थे और वह हत्या में किसी न किसी रूप से शामिल है। श्यामलाल के चचेरे भाई सत्यनारायण धाकड़ ने कहा कि खान की गतिविधियां हमेशा संदेहास्पद रही हैं और वह किसी भी हद तक जा सकती है। हालांकि उनके पास कोई ठोस सबूत कोई ठोस सबूत नहीं है,

लेकिन परिवार को संदेह है कि हत्या के पीछे महिला ही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, श्यामलाल पर धारदार हथियार से गले और मुंह पर पांच वार किए गए। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे मिले हैं। पुलिस के अनुसार, हत्या से पहले मृतक की अंतिम बातचीत भी सना खान से ही हुई थी, जिससे मामले की गुत्थी और उलझ गई है।

कॉल डिटेल रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें

हत्या के बाद सामने आई कॉल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर) ने सभी को चौंका दिया। रिपोर्ट के अनुसार, नाहरगढ़ थाना प्रभारी प्रभात गौड़ और सना खान के बीच हत्या से पहले लगातार बातचीत होती रही। यह पता नहीं चल पाया कि दोनों के बीच बार-बार क्या चर्चा होती थी, लेकिन इस लंबे संवाद ने जांच को नए मोड़ पर ला दिया है।

सीसीटीवी बंद, महिला के परिजन पहले भी आए थे धाकड़ के घर

हत्या वाले दिन गांव के मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद मिले, जिससे जांच में और जटिलता आ गई है। सूत्रों के अनुसार, कुछ समय पहले महिला सना के परिजन भी श्यामलाल के घर आए थे और उनके संबंधों पर आपत्ति जताई थी। हत्या से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में श्यामलाल और सना खान प्रेमी-प्रेमिका की तरह नजर आ रहे हैं। वीडियो के अंत में लिखा है- जान वापस आ जाओ, मुझे अकेला छोडकर कहां चले गए। वहीं, श्यामलाल के मोबाइल से सना खान के नंबर पर लगातार बातचीत होती रही।

हर एंगल से जांच

पुलिस ने इस हत्याकांड में मादक पदार्थों के व्यापार, अवैध संबंध, आर्थिक लेनदेन और पुरानी रंजिश जैसे सभा पहलुओं से जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस हत्याकांड में मादक पदार्थों के व्यापार, मुखबिरी, अवैध संबंध, आर्थिक लेनदेन और पुरानी रंजिश जैसे सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी है। मृतक के करीबी अर्जुन धाकड़, रामनिवास पाटीदार और बाबू धाकड़ से भी पूछताछ की गई है। मंदसौर एसपी अभिषेक आनंद, मल्हारगढ़ एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी, टीआई प्रभात गौड़ सहित वरिष्ठ अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। श्यामलाल की कॉल डिटेल और सोशल मीडिया अकाउंट की भी गहन जांच साइबर सेल द्वारा की जा रही है।

नशा मुक्ति के लिए थाना प्रभारी ने 103 किमी साइकिल चलाई

माही की गूंज, मंदसौर।

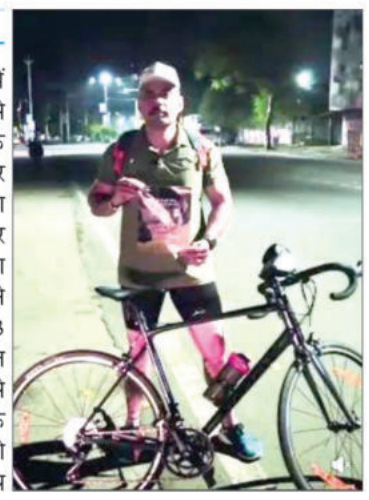

वर्तमान समय में मध्यप्रदेश पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत मंदसौर पुलिस लगातार जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। इसी कड़ी में मंदसौर सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने नवाचार करते हुए 103 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा की। उन्होंने मंदसौर से रतलाम जिले के बिलपांक थाना तक यात्रा कर लोगों को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन अपनाने का संदेश दिया।

टीआई राठौर ने बताया कि, यह यात्रा 15 जुलाई से शुरू हुए राज्य स्तरीय अभियान के प्रचार-प्रसार का हिस्सा है, जो 30 जुलाई तक चलेगा। राठौर 21 जुलाई सोमवार सुबह 4 बजे मंदसौर से साइकिल पर निकले टीआई, 6 घंटे की यात्रा कर दोपहर में रतलाम जिले के बिलपांक थाने पहुंचे। उन्होंने रास्ते में मिलने वाले लोगों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया। राठौर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते है और लगातार समाज में विभिन्न विषयों को लेकर जागरूकता लाने का प्रयास करते है। राठौर ने बताया कि नशा केवल स्वास्थ्य ही नहीं, समाज और परिवार के लिए भी नुकसानदायक है। टीआई राठौर ने कहा कि यह साइकिल यात्रा इस बात का प्रतीक है कि अगर हम चाहें तो स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। यह सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि समाज का भी दायित्व है कि युवा पीढ़ी को नशे से बचाएं।

कलेक्टर ने कृषि एवं जलसंवर्धन कार्यों का किया निरीक्षण

माही की गूंज, शाजापुर।

कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने ग्राम नारायणगांव, सामगीमाना, सतगांव, गोपीपुर एवं मझानिया का भ्रमण कर कृषि, पोषण वाटिका एवं जल संवर्धन के कार्यों का निरीक्षण किया। भ्रमण के दौरान जिला पंचायत सीईओ संतोष टैगोर, प्रभारी जनपद पंचायत सीईओ एवं डिप्टी कलेक्टर राजकुमार हलदर, कार्यपालन यंत्री पीएचई केएस डामोर, आरईएस संजय मेहर सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।

कलेक्टर सुश्री बाफना ने ग्राम नारायणगांव में कृषक राहुल पिता रमेशचंद्र के खेत का अवलोकन किया। कृषक ने फसल विविधीकरण के तहत सोयाबीन के अतिरिक्त अरहर, मक्का, मूंग और उड़द की फसल बोवनी की है। भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने क्षेत्र की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए खरीफ में उड़द और रबी के मौसम में चिया सीड जैसी फसलों को प्रोत्साहित करने की बात कही जिससे कृषक को जानवरों जैसे जंगली सूअर और नीलगाय से आने वाली समस्याएं कम होगी और बाजार में अधिक मूल्य प्राप्त होने से आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। इसी तरह कलेक्टर ने ग्राम गोपीपुर में कृषक मानसिंह एवं मनोज द्वारा फसल विविधिकरण के तहत बोई गई फसलों की जानकारी दी।

कृषकों ने बताया कि, उनके द्वारा संतरे के बगीचे में कम पानी वाली फसलें इंटरक्रॉप के रूप में लगाई जाती है। वे वर्षभर में चार फसलें लेते हैं। वही कृषकों ने बताया कि उनके द्वारा नरवाई नहीं जलाने के कारण सोयाबीन के पौधों में अपेक्षाकृत अधिक बढ़त मिली हैं। वे अन्य किसानों को अपनी फसल दिखाकर नरवाई नहीं जलाने के लिए प्रेरित भी कर रहे है। कलेक्टर ने इन प्रगतिशील किसानों को जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा खेत तालाब बनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रभारी वैज्ञानिक डॉ. जीआर अम्बावतिया, डॉ. एसएस धाकड़, डॉ. डीके तिवारी, उपसंचालक कृषि आरएल जामरे भी उपस्थित थे। ग्राम गोपीपुर में हितग्राही गणपतसिंह पिता रामेश्वर द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्मित खेत तालाब का भी कलेक्टर ने निरीक्षण किया।

इसी तरह ग्राम सामगीमाना एवं सतगांव की आंगनवाड़ी केन्द्रों में कलेक्टर ने तैयार की जा रही पोषण वाटिका का निरीक्षण किया। साथ ही इन स्थलों पर कलेक्टर ने पौधरोपण भी किया। ग्राम मझानिया में कलेक्टर ने शांतिवन में किये गये पौधरोपण कार्य का निरीक्षण किया एवं स्वयं भी पौधा लगाया। इस दौरान सतगांव में सरपंच संजय पाटीदार, मझानिया में सरपंच श्रीमती राजुबाई रजावत तथा सीडीपीओ सुश्री नेहा चौहान भी उपस्थित थी।

विधि महाविद्यालय की मरम्मत का कार्य शीघ्र पूरा करें

इसी दौरान कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने शासकीय विधि महाविद्यालय शाजापुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हवा के दबाव से टूटी खिड़कियों एवं छत से पानी के लीकेज होने की समस्या का स्थायी हल ढूंढने तथा मरम्मत करने के निर्देश निर्माण ऐजेंसी पीआईयू को दिये। इस दौरान कलेक्टर ने कक्षों का निरीक्षण कर छात्रों की उपस्थिति एवं प्रवेश की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. एमके कनेरिया, कार्यपालन यंत्री पीआईयू श्री भाक्या परमार भी उपस्थित थे।

कच्ची घानी से खाद्य तेल के उत्पादन का निरीक्षण

कलेक्टर सुश्री बाफना ने शाजापुर नगर के काशीनगर में हितग्राही हिमांशु श्रीवास्तव द्वारा उद्यानिकी विभाग की पीएमएफएमई योजना के तहत लगाई गई कच्ची घानी तेल यूनिट का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने हितग्राही श्री हिमांशु से उत्पादन एवं विक्रय की जानकारी ली। कलेक्टर ने उत्पादित तेल का संग्रहण काँच की बोतलों में करने एवं साफ-सफाई का ध्यान रखने के लिए कहा। इस दौरान उपसंचालक उद्यान मनीष चौहान एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रभारी डॉ. जीआर अम्बावतिया भी उपस्थित थे।

वन विभाग ने गोह अंग तस्कर गैंग को दबोचा, 3 गिरफ्तार

माही की गूंज, मंदसौर।

गांधीसागर में चीतों को लाने के बाद मंदसौर वनमंडल में वन विभाग ने संदिग्धों पर अपनी निगाहें गढा दी है। इस काम के लिए आधुनिक संसाधनों के साथ ही मुखबिरों का उपयोग लिया जा रहा है।

इसी कडी में मंदसौर वन विभाग ने गोह के शरीर के अंगों की तस्करी करने वाली गैंग के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 42 जोड़ी शरीर के अंगों, जिसे ÷हत्था जोड़ी÷ कहा जाता है बरामद की है। वनमंडल अधिकारी, सामान्य वनमंडल मंदसौर संजय रायखेरे ने बताया कि मंदसौर के अंतर्गत वनपरिक्षेत्र भानपुरा में रविवार को वन्यजीवों के अवैध व्यापार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई।

वन विभाग ने गोह के शरीर के अंगों, जिसे ÷हत्था जोड़ी÷ कहा जाता है, की तस्करी करने के आरोप में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह सफल ऑपरेशन उप वनमंडलाधिकारी, गरोठ के परिक्षेत्र भानपुरा में अंजाम दिया गया।

वनकर्मी बना ग्राहक और जाल में फंसाया

वन विभाग को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग मॉनिटर लिजार्ड के शरीर के हिस्से हत्था जोड़ी बेचने की फिराक में हैं। सूचना पर कार्यवाही करते हुए वन स्टाफ ने एक कर्मचारी को ग्राहक बनाकर संदिग्धों से मिलने भेजा। पूर्व नियोजित इशारे पर वन अमले ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दो संदिग्धों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया।

संदिग्धों की तलाशी लेने पर उनके पास से 42 नग हत्था जोडी, एक चाकू और कुछ नकदी बरामद हुई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान विजय पिता रमेश निवासी ग्राम तोरनिया नाहरगढ़ तहसील भानपुरा जिला मंदसौर एवं समरथनाथ पिता सिंघानाथ निवासी ग्राम हनुमंतीया, कुकडेश्वर तहसील, मनासा जिला नीमच के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ के बाद, इस मामले से जुड़े एक और संदिग्ध करण उर्फ धर्मा हरिजन निवासी कुकडेश्वर तहसील, मनासा जिला नीमच को भी हिरासत में लिया गया है।

गोह अनुसूची 1 के तहत संरक्षित-

गोह को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत् संरक्षित किया गया है और लुप्तप्राय प्रजातियो में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किया गया है जो जानवर या उसके शरीर के अंगो के आयात या निर्यात को प्रतिबंधित करता है। इस मामले में आरोपीयो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर आगे की विस्तृत जांच और आवश्यक कानूनी कार्यवाही जारी है।

मंदिर में कोबरा के 10 बच्चों ने जमाया डेरा

माही की गूंज, रतलाम।

जिले के सैलाना कस्बे से रविवार को एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। यहां महालक्ष्मी मंदिर परिसर में एक साथ कोबरा सांप के 10 बच्चे निकलने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया।

यह पूरा घटनाक्रम उस वक्त सामने आया, जब मंदिर के पुजारी ने नियमित पूजा से पहले मंदिर में सफाई करते समय दीवार के एक पुराने छेद में कुछ हलचल महसूस की। पुजारी ने जब ध्यान से देखा, तो छेद के भीतर एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 10 छोटे-छोटे कोबरा के बच्चे मौजूद थे। यह नजारा देखकर पुजारी घबरा गए और तुरंत आसपास के लोगों को बुलाकर घटना की जानकारी दी। देखते ही देखते मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ जुट गई।

दर्शन के लिए पहुंचे लोग

इस दौरान सावन मास चलने के कारण मंदिर में पहले से ही भक्तों की आवाजाही थी, लेकिन जैसे ही नाग के बच्चों की खबर फैली, लोग इसे भगवान शिव के प्रतीक 'नाग देवता' का चमत्कार मानते हुए मंदिर पहुंचने लगे। श्रद्धालु नागों के दर्शन को पुण्यदायी मानते हुए घंटों मंदिर में डटे रहे।

जंगल में छोड़ दिए गए सभी सांप

इसके बाद घटना की जानकारी सर्पमित्रों को भी दी गई, जिनकी सहायता से कोबरा के सभी बच्चों को सुरक्षित तरीके से पकड़ कर जंगल में छोड़ दिया गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान विशेष सावधानी बरती गई, ताकि सांपों को कोई नुकसान न पहुंचे।

जहां मिले सांप, उस दीवार की कराई गई मरम्मत

ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर परिसर में पहले भी सांप दिखने की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन एक साथ कोबरा के इतने बच्चे पहली बार देखने को मिले हैं। इस घटना के बाद मंदिर प्रबंधन ने दीवार के उस हिस्से की मरम्मत कराने का निर्णय लिया है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके।

फिलहाल, मंदिर परिसर को साफ-सुथरा कर सुरक्षित बना दिया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें श्रद्धालु नाग देवता के दर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं। मंदिर में मौजूद बुजुर्गों ने इसे शुभ संकेत माना है।

10 वर्षीय बालक जिष्णु दवे के नाम एक साथ दर्ज हुए तीन विश्व रिकॉर्ड

माही की गूंज, रतलाम।

रतलाम के 10 वर्षीय बालक जिष्णु दवे ने कम उम्र में वह कर दिखाया है जो बड़े-बड़े भी नहीं कर पाते। आध्यात्मिक रुचि और रुद्राक्षों के प्रति विशेष आकर्षण के चलते जिष्णु ने एक साथ तीन विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर रतलाम और देश का नाम रोशन किया है।

जिष्णु दवे बचपन से ही रुद्राक्षों के प्रति गहरी जिज्ञासा रखते हैं। मात्र 5 वर्ष की आयु से ही जब भी रुद्राक्षों का वितरण या संग्रह होता, वह स्वयं उनमें से विशेष चिन्ह जैसे ?(ओम), त्रिशूल, स्वस्तिक, सुदर्शन आदि वाले रुद्राक्ष पहचानने में रुचि लेते थे। अब तक जो भी दुर्लभ रुद्राक्ष संग्रह में आए हैं, वे अधिकतर जिष्णु की खोज का परिणाम हैं। इन विशेषताओं के आधार पर जिष्णु के नाम तीन विश्व रिकॉर्ड दर्ज हुआ हैं।

दुनिया का सबसे बड़ा रुद्राक्ष - 6.6 सेमी आकार और 120 ग्राम वज़न का यह रुद्राक्ष वाराणसी से मंगवाया गया था। इसे पहले कोई रिकॉर्ड में नहीं जोड़ा गया था। ?(ओम) चिह्न वाले 25 रुद्राक्षों का संग्रह - यह अपने आप में एक दुर्लभ आध्यात्मिक संग्रह है।दुर्लभ रुद्राक्षों का संकलन - जिसमें बिना रेखाओं वाला रुद्राक्ष, त्रिशूल, स्वास्तिक, नागेश्वर लिंगम् और सुदर्शन चिह्न वाले रुद्राक्ष शामिल हैं।

इन तीनों रिकॉर्ड को यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ यूएन , एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा आधिकारिक रूप से प्रमाणित किया गया है।

विनोबा नगर निवासी जिष्णु दवे रतलाम के गुरु रामदास पब्लिक स्कूल में कक्षा 5 का छात्र है तथा ज्योतिषाचार्य महर्षि संजय शिवशंकर दवे का सुपुत्र है।

इस अद्भुत उपलब्धि पर रतलाम के अखण्ड ज्ञान आश्रम में एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वेब वर्ल्ड रिकॉर्ड के जूरी मेंबर शैलेन्द्र सिंह सिसौदिया, कमलेश जोशी ने संतों के सानिध्य में बालक को सम्मान पत्र भेंट किया। इस अवसर पर श्रृंगेरी मठ के दंडी स्वामी आत्मानंद जी सरस्वती, अखंड ज्ञान आश्रम के महामंडलेश्वर देवस्वरूपानंद जी महाराज, स्वामी सुज़ानानंद जी महाराज, स्वामी प्रभुतानंद जी महाराज , स्वामी सास्वता नंद जी महाराज , स्वामी सुदामा जी मिश्रा , निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा शर्मा सहित संतों एवं गणमान्य नागरिकों , मनोज शर्मा , श्रीश्रीमाली ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष नयन व्यास , सचिव कुलदीप त्रिवेदी ,राजेन्द्र पुरोहित , राजेश पाण्डेय ,पतंजलि से विशाल कुमार वर्मा ,पं.संजय मिश्रा सोमेश शर्मा , सौरभ शर्मा ने उपस्थित होकर जिष्णु दवे को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दीं।

रतलाम का यह होनहार बालक आध्यात्मिक चेतना और रुद्राक्ष के प्रति निष्ठा से आज पूरे भारत के लिए प्रेरणा बन गया है। जानकारी पंडित संजय शिव शंकर दवे ने दी।

बदहाल स्वास्थ्य केंद्रः दो महीने से डॉक्टर नहीं, एक्स-रे मशीन भी खराब, ग्रामीण परेशान

माही की गूंज, सारंगी। संजय उपाध्याय

सारंगी में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है। पिछले दो महीनों से स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में न तो कोई डॉक्टर है और न ही एक्स-रे मशीन काम कर रही है। जिससे ग्रामीणों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बार-बार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से गुहार लगाने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है।

ग्रामीणों के अनुसार, सारंगी का स्वास्थ्य केंद्र लगभग दो महीने से पूरी तरह से डॉक्टर विहीन है। सामान्य बीमारियों के इलाज से लेकर प्राथमिक चिकित्सा तक के लिए लोगों को दर-दर भटकना पड़ रहा है। छोटे-मोटे बुखार, खांसी, या चोट लगने पर भी उन्हें मजबूरन आसपास के बड़े शहरों जैसे पेटलावद या झाबुआ का रुख करना पड़ रहा है, जिसमें न केवल अतिरिक्त समय और पैसा खर्च होता है, बल्कि कई बार आपातकालीन स्थिति में मरीजों की जान पर भी बन आती है। विशेष रूप से बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, जिन्हें अक्सर तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है।

खराब एक्स-रे मशीन ने बढ़ाई मुश्किलें

डॉक्टरों की अनुपस्थिति के साथ-साथ, स्वास्थ्य केंद्र में लगी एक्स-रे मशीन भी लंबे समय से खराब पड़ी है। हड्डी टूटने या आंतरिक चोटों जैसी स्थितियों में एक्स-रे की आवश्यकता होती है, लेकिन मशीन खराब होने के कारण मरीजों को फिर से निजी क्लीनिकों या दूर के अस्पतालों में जाना पड़ता है। यह स्थिति उन गरीब ग्रामीणों के लिए और भी कठिन हो जाती है, जो निजी अस्पतालों का महंगा खर्च वहन करने में असमर्थ हैं।

प्रशासन पर ग्रामीणों का रोष

ग्रामीणों में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के प्रति भारी रोष है। उनका कहना है कि, कई बार लिखित और मौखिक रूप से शिकायतें की गई हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि, यदि जल्द ही डॉक्टरों की नियुक्ति और एक्स-रे मशीन की मरम्मत नहीं की गई, तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सारंगी जैसी स्थिति, जहां मूलभूत सुविधाएं भी नदारद हैं, स्वास्थ्य प्रणाली की खामियों को उजागर करती है और तत्काल ध्यान देने की मांग की जा रही है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन उनकी इस गंभीर समस्या पर गौर करेगा और जल्द से जल्द समाधान निकालेगा।

सारंगी में डॉक्टरों की कमी की बात सामने आई है। इस बात की जानकारी है और वे जल्द से जल्द व्यवस्था कर रहे हैं, और डॉक्टर की नियुक्ति के लिए मैंने उच्च अधिकारियों से बात की है।

डॉ एमएल चोपड़ा बीएमओ पेटलावद।

552 मीटर लंबा ओवरब्रिज बनकर हुआ तैयार, ट्रैफिक से मिलेगी अब निजात

माही की गूंज, रतलाम।

रतलाम शहर में आखिरकार 5 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद 552 मीटर लंबा ओवरब्रिज बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस और ब्रिज के निर्माण से शहर के लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी। बता दें कि रतलाम शहर में 5 साल में 552 मीटर लंबा सुभाष नगर ओवरब्रिज बन पाया है। रंगाई-पुताई भी हो गई है।

वाहन भी गुजरने लगे हैं। अब सिर्फ बिजली, रोड मार्किंग जैसे छोटे काम चल रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स लगाने के बाद उसका अलग से अलग से ट्रांसफार्मर भी लगा दिया है। बिजली मीटर लगने के लिए मंगलवार को मप्र विद्युत वितरण कंपनी से परमिशन भी मिल जाएगी। कनेक्शन होते ही ब्रिज की लाइट्स भी चालू कर दी जाएंगी।

2 दिन में हो जाएगा रोड मार्किंग का कार्य पूर्ण

इस ओवरब्रिज पर एक-दो दिन में रोड मार्किंग भी कर दी जाएगी। इसमें पेंट से सेंटर लाइन और साइड लाइन डाली जाएगी। ये काम पूरा होते ही आरओबी का काम पूरा हो जाएगा। उधर दोनों तरफ की एप्रोच रोड बनने के बाद इससे वाहनों का गुजरना शुरू हो गया है।

ब्रिज तैयार होने में लगा 5 वर्ष का समय

इस ब्रिज को बनाने में सेतु विकास निगम ने पांच साल लगा दिए हैं। मार्च में हुई दिशा समिति की बैठक में इसे पूरा करने के लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन तय की गई थी। उसे गुजरे भी लगभग तीन माह होने को आए हैं। बता दें कि आरओबी का काम जून 2020 में प्रारंभ हुआ था।

ट्रांसमिशन लाइनों के पास हो रहे अवैध निर्माण से जान का खतरा बढ़ा

माही की गूंज, खरगोन।

खरगोन शहर और उसके आसपास के इलाकों में तेज़ी से हो रहे अनाधिकृत निर्माण अब आम लोगों की जान के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की 132 से लेकर 220 किलोवोल्ट तक की छह प्रमुख विद्युत लाइनें इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। इन लाइनों के आसपास लगातार ऐसे निर्माण हो रहे हैं, जो बिजली सुरक्षा नियमों के विरुद्ध हैं। इन निर्माणों के कारण न केवल बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है, बल्कि आम नागरिकों की जान पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

खरगोन के ओंकार दत्त रेजिडेंसी, निमरानी, द्वारका धाम कॉलोनी, साकेत नगर, जैतापुर, यमुना नगर कॉलोनी, मोतीपुरा, हिंगलाज नगर, स्मार्ट पार्क टाउनशिप, माँ रेवा विन्यास कॉलोनी, पानवा और भीलगांव जैसे इलाकों में ट्रांसमिशन लाइनों के बेहद करीब मकान और अन्य निर्माण कार्य हो चुके हैं। इन इलाकों में बिजली की तारों और निर्माणों के बीच सुरक्षित दूरी नहीं रखी गई है, जिससे करंट लगने, स्पार्किंग और आग लगने जैसी दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती हैं।

खरगोन जिले में छह मुख्य ट्रांसमिशन लाइनें हैं, जिनके पास नियमों के विरुद्ध निर्माण हो चुके हैं। इनमें भीकनगांव-खरगोन, बिस्टन-लिलो, निमरानी-कसरावद, निमरानी-छैगांव, निमरानी-ओंकारेश्वर और महेश्वर-पीथमपुर लाइनें शामिल हैं। इन सभी स्थानों पर बिजली सुरक्षा के नियमों को नजरअंदाज करते हुए घर, दुकानें और अन्य संरचनाएं बना दी गई हैं।

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अनुसार, अब तक 85 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कंपनी के कार्यपालन यंत्री वीर सिंह भूरिया ने बताया कि लोगों को इन निर्माणों को हटाने और भविष्य में इस तरह की गलती न दोहराने की सख्त चेतावनी दी गई है। यदि नोटिस के बाद भी निर्माण नहीं हटाए गए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बिजली विभाग के अनुसार, 132 किलोवोल्ट या उससे अधिक क्षमता वाली ट्रांसमिशन लाइनों के नीचे कम से कम 27 मीटर की खाली जगह होना जरूरी है, ताकि हवा में झूलते तारों से कोई संपर्क न हो और जान-माल की हानि से बचा जा सके।

जानकारों का कहना है कि घरेलू बिजली की तीव्रता मात्र 230 वोल्ट होती है, जो स्वयं में जानलेवा हो सकती है। वहीं ट्रांसमिशन लाइनों में 132,000 से 2,20,000 वोल्ट तक का प्रवाह होता है, जो कि 600 से 950 गुना अधिक है। ऐसे में इन हाई वोल्टेज तारों के नीचे या आसपास निर्माण करना एक बहुत बड़ा जोखिम है।

इन अवैध निर्माणों से न केवल कानून का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि हजारों लोगों की जान को भी खतरे में डाला जा रहा है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना होना तय है।

बाबा बर्फानी के दर्शन कर घर पहुंचे श्रद्धालु

माही की गूंज, सारंगी।

सावन माह में बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सारंगी पेटलावद से 35 श्रद्धालुओं का जत्था सकुशल अपने घर पहुंचे। सभी भक्त 7 जुलाई को उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन कर जम्मू पहुंचकर बालटाल के रास्ते पैदल चढ़ाई कर बाबा अमरनाथल के दर्शन किए। सभी श्रद्धालुओं ने 14 दिन की यात्रा में माता वैष्णो देवी, शिवखोड़ी धाम, श्रीनगर अमृतसर, जम्मू घूमते हुए अपने घर पहुंचे। श्रद्धालु जब अपने घर सारंगी पहुंचे यहां पर ग्रामवासियों ने स्वागत कर सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दी।

आवास योजना की रफ्तार सुस्त, ग्रामीण अब भी कर रहे इंतजार

माही की गूंज, बड़वानी।

जिले की अंजड़ तहसील के सुराना गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने की आस लगाए बैठे ग्रामीणों को अब तक सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। पिछले कई वर्षों से गांव में न तो कोई नया आवास बना है और न ही किसी लाभार्थी को पहली किस्त प्राप्त हुई है।

पंचायत सचिव एम. एस. परिहार के अनुसार अब तक लगभग 140 लोगों को योजना का लाभ मिल चुका है, जबकि 415 अन्य ग्रामीण अभी भी लाभ से वंचित हैं। लगभग 300 लोगों का सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। कुछ लोगों के पक्के मकान पाए जाने के कारण उनके नाम सूची से हटा दिए गए। वहीं, कुछ लाभार्थियों को पहली किस्त मिल चुकी है, लेकिन मकान निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।

जहाँ एक ओर देशभर में इस योजना के तहत लाखों आवासों का निर्माण हो चुका है, वहीं सुराना गांव में इसका कार्य बेहद धीमा है। स्थानीय प्रशासन को इस दिशा में गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है।

मृत, सेवानिवृत्त और प्रशिक्षु शिक्षकों के भी तबादले...!

माही की गूंज, खरगोन।

खरगोन जिले में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किए गए शिक्षकों के तबादलों को लेकर कांग्रेस ने भारी अनियमितताओं और लेन-देन के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रवि नाईक ने दस्तावेज़ों के आधार पर आरोप लगाया कि इन तबादलों में स्थानांतरण नीति का पालन नहीं किया गया। कई स्थानांतरणों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, जिसके बाद उन्हें स्थगित कर दिया गया है।

रवि नाईक ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित स्थानांतरण नीति की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। कुछ ऐसे शिक्षक जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम भी स्थानांतरण सूची में शामिल हैं। वहीं, कुछ ऐसे शिक्षक जो सेवा निवृत्ति के निकट हैं या अभी प्रशिक्षु अवधि में हैं, उनका भी तबादला कर दिया गया है।

नाईक ने यह भी बताया कि कुछ स्कूल जो पहले ही अन्य विद्यालयों में समाहित (विलय) किए जा चुके हैं, वहां भी शिक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। यह स्पष्ट करता है कि तबादले बिना किसी भौतिक सत्यापन और वास्तविक आवश्यकता के किए गए हैं।

कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि स्थानांतरण और फिर उन्हें निरस्त करने के नाम पर विभाग में व्यापक लेनदेन हुआ है। नाईक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और प्रभारी मंत्री इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं।

100 से अधिक तबादलों पर उच्च न्यायालय की रोक

अब तक जिले में 100 से अधिक स्थानांतरण आदेशों पर उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किया है। कांग्रेस ने मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और स्थानांतरण सूची को निरस्त कर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

इस मामले में जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त इकबाल आदिल ने कहा कि सभी तबादले स्थानांतरण नीति के अनुरूप किए गए हैं और किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। कुछ शिक्षकों ने न्यायालय का रुख किया था, जहां उन्हें कुछ सप्ताह के लिए स्थगन आदेश प्राप्त हुए हैं।

नैतिकता और अभिव्यक्ति की आज़ादी के यक्ष प्रश्न

ज्योति मल्होत्रा

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया बेहद दिलचस्प व्यक्ति हैं। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वे हिंदी फ़िल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया के बड़े भाई हैं- जिन्होंने गैंग्स ऑफ़ वासेपुर, पान सिंह तोमर, साहिब बीवी और गैंगस्टर आदि फिल्में बनाई- बल्कि इसलिए कि उनमें आपको एक नेकनीयत गुस्सा दिख सकता है, जो उनके फ़ैसलों में झलकता है। जिनमें बुराई को सज़ा व अच्छाई को राहत मिलती दिखती है, या फिर, सबसे महत्वपूर्ण है अपनी पसंद-नापसंदगी की आजादी का विचार, जो संविधान में दिया मूलभूत अधिकार है, वह खामोशी से उनके फैसलों में खुद को दोहराता है।

उन्हें नायक में तबदील किए जाने के खतरे के बावजूद, वे नायक बनने की काबिलियत रखते हैं। हम जैसे लोगों ने इस अप्रैल में उनके द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के दिए एक फैसले को बरकरार रखने की सराहना की थी, जिसमें एक दुष्ट माता-पिता को अपनी ही बेटी-दामाद की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया ('एक क्रूर और घिनौना जुम...गहरे तक जड़ें जमाए जातिवाद की कुरूप सच्चाई')। अप्रैल में ही, धूलिया ने सवाल किया था कि महाराष्ट्र की एक नगरपालिका में उर्दू को लेकर इतना पूर्वाग्रह क्यों कायम है ('यह पूर्वाग्रह इस धारणा से उपजा कि उर्दू भारत में विदेशी है...यह सोच गलत है'); और 2022 में, उन्होंने कर्नाटक सरकार के उस फैसले के खिलाफ एक विभाजित फैसला दिया, जिसमें मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने से रोक दिया गया था ('यह पसंद का मामला होना चाहिए...अंतरात्मा, आस्था एवं अभिव्यक्ति का मामला')।

वैसे सुप्रीम कोर्ट में अन्य 'सितारे' भी हैं - पिछले हफ्ते, हरियाणा के जस्टिस सूर्यकांत, जो जल्द अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं,उन्होंने देश के युवा दिलों को खुशी से भर दिया, जब अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली महमूदाबाद के मामले में हरियाणा के पुलिस कर्मियों को फटकार लगाई - पुलिस ने अली के सभी डिवाइस जब्त कर लिए थे और पिछले 10 वर्षों में उनकी विदेश यात्राओं का ब्योरा मांगते हुए, उनके कथित अपराध (ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग हेतु एक मुस्लिम महिला को प्रवक्ता चुनने पर सरकार को निशाना बनाती सोशल मीडिया पोस्ट्स) की जांच का दायरा बढ़ाने पर।

ये वही जस्टिस सूर्यकांत हैं, जिन्होंने मार्च में कॉमेडियन रणवीर अल्लाहबादिया मामले में नाना विशेषण ('घृणित' और 'अपमानजनक') दिए थे, जब रणवीर ने मां-बाप को लेकर भौंडा मज़ाक किया था। तब, जस्टिस सूर्यकांत ने अभिव्यक्ति की आज़ादी और अश्लीलता के बीच सदा एक रेखा कायम रखने की नसीहत दी थी। मई में कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग करने में दिशा-निर्देश ज़रूरी हैं। गत हफ़्ते की शुरुआत में, न्यायमूर्ति सूर्यकांत का रूप खुलकर सामने आया। जीवन एवं स्वतंत्रता के हक से संबंधित अनु.21 को लेकर उन्होंने कहा कि इसका अधिमान बोलने एवं अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े अनु. 19 से अधिक है, और रहेगा। न्यायाधीश महोदय मामले के मर्म को टटोल रहे थे - अधिकारों और कर्तव्यों के बीच टकराव। स्पष्टतया, उनका मानना था कि कुछ मौलिक अधिकार दूसरों की तुलना में अधिक मौलिक हैं।

निश्चित रूप से, हमारे संस्थापक पुरखों ने युगों-युगों तक रहने वाली इस दुविधा के बारे में सोचा होगा। इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 19 (1) में दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी पर कुछ अंकुश लगाते हुए, फौरन अगले अनुच्छेद 19 (2) में कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी संपूर्ण नहीं, और भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, जन व्यवस्था या नैतिकता के हित में इस पर उचित अंकुश होने चाहिए।

अंतिम वाक्यांश के बारे में, सवाल है कि क्या समलैंगिकता को अपराध घोषित किया था, जिसे अंततः 2018 में हटा दिया गया, तो पूर्व भाजपा नेता अरुण जेतली, जो जाने-माने वकील भी थे, ने अपने साथी पार्टी नेताओं को समझाया कि अगर समान लिंग के कुछ लोग आपस में यौन संबंध बनाते हैं तो इससे कोई आसमान टूटने वाला नहीं है।

इसी तरह, जब माननीय न्यायाधीश को वास्तविक जीवन में अभिव्यक्ति की आजादी के मोल का भान अच्छी तरह है, तो सोशल मीडिया के मामले में इसको अलग ढंग से क्यों बरता जाए? क्या अली महमूदाबाद की पोस्ट्स अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा थीं या फिर महिलाओं को अपमानित करने का नुस्खा, जैसा कि एक भाजपा नेता का मानना था? सोशल मीडिया की वे टिप्पणियां जो किसी के लिए बहुत ज़्यादा अपमानजनक हैं या अन्यों के लिए इतनी कि संख्या गिनने में न आए। फिर एक मामला है कुणाल कामरा का, जिसने कथित तौर पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पर 'गद्दार' या 'देशद्रोही' का तंज कसा था। ऐसे ही कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने एक कविता पढ़ी, जो गुजरात में किसी को नागवार लगी और उसने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। जहां तक रणवीर अल्लाहबादिया के 'मां-बाप' किस्म के चुटकुलों की बात है, लोकप्रिय 'सेल्फ़ी विद डॉटर' अभियान दृ जिसको बढ़ावा देने वालों में खुद प्रधानमंत्री मोदी शामिल हैं - उसके द्वारा करवाया गया 'गाली बंद' नामक सर्वे बताता है कि मां-बहन की गालियां सबसे ज़्यादा दिल्ली वाले (80 फीसदी) इस्तेमाल करते पाए गए, उसके बाद नंबर रहा पंजाब (78 फीसदी), उत्तर प्रदेश और बिहार (74 फीसदी) और राजस्थान (64 फीसदी) का।

केवल सोशल मीडिया पर नहीं, उत्तर भारतीय मर्द बातचीत में किस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करते हैं काश माननीय सुप्रीमकोर्ट इसका भी संज्ञान लेता। शायद, मामले की जड़ यह है कि हम ऐसे ही हैं - हालांकि जो दिल में आया उसे कहने वालों को निशाना बनाने की यह कोई वजह नहीं हो सकती।

मई में, जब अली का मामला पहली बार सर्वोच्च न्यायलय आया, तो जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा कि अगर छात्र और प्रोफेसर 'कुछ भी करने की हिमाकत करेंगे...अगर वे आपस में हाथ मिलाने जैसी कोशिश करेंगे, तो हमें बखूबी पता है कि इनसे कैसे निबटना है, वे हमारे अधिकार क्षेत्र में हैं'।

आप हमारे नायक बनने जा रहे जस्टिस धूलिया पर भी ऐसा ही आक्षेप लगा सकते हैं। जब इस महीने की शुरुआत में मध्य प्रदेश के एक कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम ज़मानत मांगी, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट उनकी गिरफ़्तारी को मंजूरी दे रहा था - प्रधानमंत्री मोदी पर 2021 में बनाए गए एक कार्टून को लेकर, जिसे भौंडा माना गया था - तो जज भड़क गए। जस्टिस धूलिया ने कहा, 'हद है! लोग किसी को भी, कुछ भी कह देते हैं'।

अब जबकि हमारी आंखों पर पड़ा पर्दा हट गया है और हम अपने भावी नायक को स्तब्ध होकर देख रहे हैं, अनायास ही यह विचार उभर आता है- अगर सुप्रीम कोर्ट भी हमें अपनी वाणी, अपने चित्रों, कविताओं, संगीत, फिल्मों, अपने विचारों की अभिव्यक्ति पर खुद ताला लगाने को कह दे, तो हम सुरक्षा के लिए कहां जाएं?

इसलिए,पिछले हफ़्ते की सबसे बड़ी दुविधा यही मुद्दा रहा। भारत का रूढ़िवादी और सामंती समाज, जिसने विभाजन के आघातों के आलोक में, नेहरू और उनके साथियों को राष्ट्रीय विचारधारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे समतावादी सिद्धांतों की ओर जाने की अनुमति दी थी, अब पिछले एक दशक में कट्टर दक्षिणपंथ की और वापसी में खुशी-खुशी शामिल हो गया है। अब इस पर रिवर्स गियर कैसे लगाया जाए?

महाकाल की नगरी में राजनीतिक तूफान

माही की गूंज, उज्जैन।

उज्जैन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाकाल मंदिर के प्रशासक कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इंदौर-3 से भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए।

साथ ही, उन्होंने महाकाल मंदिर के प्रशासक से इस्तीफे की भी मांग की। मामला श्रावण माह के दूसरे सोमवार का है, जब भस्म आरती के दौरान विधायक शुक्ला और उनके पुत्र रुद्राक्ष कथित रूप से मंदिर के गर्भगृह में जबरन प्रवेश कर गए थे।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मंदिर के गर्भगृह में जबरन प्रवेश कर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। उनका कहना है कि इस मामले में महाकाल मंदिर के प्रशासक तत्काल पद से इस्तीफा दें और विधायक के पुत्र के खिलाफ त्वरित गिरफ्तारी एवं कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी मांग उठाई कि यह स्पष्ट किया जाए कि विधायक को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति आखिर किस अधिकारी ने दी।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता ने तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि क्या अब महाकाल मंदिर बीजेपी नेताओं की निजी संपत्ति बन गया है? उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री, विधायक और उनके परिजन गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं, जबकि आम

श्रद्धालुओं के लिए वहां जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

प्रशासनिक सुस्ती से बढ़ा असंतोष

नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि, हम मंदिर समिति के सदस्यों से यह अपील करने आए हैं कि बीजेपी विधायक और उनके पुत्र द्वारा गर्भगृह में जबरन प्रवेश कर वहां मौजूद अधिकारियों और पुजारियों से अभद्रता करना न केवल अनुचित है, बल्कि निंदनीय भी है। ऐसे व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी मामला दर्ज किया जाए।

यह वही विधायक पुत्र हैं, जिन्होंने देवास के मां चामुंडा के दरबार में रात 12:30 बजे मंदिर खुलवाया था और पुजारी के साथ धक्का-मुक्की की था। उस मामले में देवास जिला प्रशासन ने तत्काल एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन इस बार उज्जैन जिला प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है।

हमारी मांग है कि जांच समिति में केवल निष्पक्ष और स्वतंत्र व्यक्तियों को शामिल किया जाए। पिछली बार भी एक समिति का गठन तो हुआ था, लेकिन वह महज औपचारिकता साबित हुई और उसका कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया।

हमारी स्पष्ट मांग है कि किसी भी नई जांच समिति में निष्पक्ष और विश्वसनीय व्यक्तियों को ही शामिल किया जाए। पिछली बार भी एक समिति का गठन केवल औपचारिकता के लिए किया गया था, लेकिन वह किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी।

गर्भगृह में प्रवेश पर उठे सवाल

करीब दो साल पहले महाकाल मंदिर की देहरी तक पहुंचने को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद माया त्रिवेदी के खिलाफ मंदिर समिति ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। माया त्रिवेदी ने कहा कि एक समय ऐसा भी आया जब मुझे मंदिर की देहरी तक जाने की भी अनुमति नहीं दी गई। मुझे धरने पर बैठना पड़ा, तभी मुझे जल अर्पण करने की इजाज़त मिली। इतना सख्त रवैया अपनाया गया, और जब उन्हें यह पता चला कि मैं कांग्रेस से हूं, तो मुझे रोक दिया गया।

उन्होंने तीखा आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे महाकाल मंदिर पर अब भाजपा का एकाधिकार हो गया है। केवल भाजपा के मंत्री, विधायक और उनके परिजनों को ही गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी जाती है, जबकि आम श्रद्धालुओं के लिए यह मार्ग पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

मास्टर ट्रेनर्स हेतु एक दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग का आयोजन

माही की गूंज, अलीराजपुर।

जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित सक्षम कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के सभी 6 ब्लॉकों के मास्टर ट्रेनर्स हेतु एक दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग का आयोजन सहायक आयुक्त कार्यालय मे किया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य मास्टर ट्रेनर्स की दक्षता में वृद्धि करना, पाठ्यक्रम की समझ को सुदृढ़ करना तथा उनके उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से साझा करना था, ताकि वे फील्ड में सशक्त रूप से अपने कार्य को पूर्ण कर सकें। प्रशिक्षण में द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम की समझ, डेमो और सत्र अभ्यास, जेंडर संवेदनशीलता, एमटी की भूमिका और उत्तरदायित्व,एक्शन प्लान निर्माण आदि मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण के दौरान कार्यालय में सेकंड ईयर पाठ्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा पर गहन चर्चा की गई, सभी मास्टर ट्रेनर्स के साथ डेमो सत्र भी प्रस्तुत किया गया। इस प्रशिक्षण में तकनीकी, टाईम मैनेजमेंट और प्रतिभागियों पर फोकस, जेंडर इक्विटी आदि विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान सभी मास्टर ट्रेनर्स एवं सक्षम कार्यक्रम के तहत अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

बावड़ी की दीवार की खोदाई में निकला प्राचीन कोल्हू

माही की गूंज, धार।

शताब्दियों पूर्व के समृद्ध इतिहास के साक्षी मांडू नगर में उत्खनन में प्राचीन वस्तुएं निकलती रहती हैं। अब यहां प्राचीन चतुर्भुज श्रीराम मंदिर परिसर स्थित हनुमान मंदिर के पीछे बावड़ी की दीवार से भारी भरकम कोल्हू प्राप्त हुआ है। इतिहासकार इसे 17वीं शताब्दी का बता रहे हैं। यहां राम मंदिर परिसर में संकट मोचन हनुमान मंदिर के पीछे बावड़ी की दीवार से प्राप्त होने के बाद कोल्हू को मंदिर परिसर में रखा गया है।

मंदिर की बावड़ी की दीवार की मरम्मत के समय अद्भुत संरचना दिखाई दी। गुरुवार को कोल्हू को बाहर निकाला गया। फिलहाल मंदिर परिसर में ही इसे उपयुक्त स्थान पर रख दिया गया है।

कोल्हू जैसी है संरचना, तेल निकालने में होता था उपयोग

राज्य पुरातत्व विभाग के संग्रहालय अध्यक्ष और पुरातत्वविद डॉ. आरपी पांडे ने बताया कि, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि यह कोल्हू है। इसका उपयोग प्राचीन काल में तेल निकालने के लिए किया जाता था। बैलों के गले में रस्सी बांधकर इस संरचना से तेल निकालने की प्रक्रिया की जाती थी। प्राचीनकाल में बड़े स्तर पर यह उपयोग में लाया जाता था।

बड़ा व्यापारिक केंद्र था मांडू, विदेश में होता था निर्यात

डॉ. पांडे का कहना है कि, मांडू 17वीं शताब्दी में तेल और महत्वपूर्ण वस्तुओं के निर्यात का बड़ा केंद्र था। यहां गधाशाह नामक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। आज भी मांडू में गधाशाह का महल स्थित है। इसे गधाशाह की दुकान कहते हैं। इस काल में मांडू दुनिया का बड़ा व्यापारिक केंद्र था।

विदेश तक यहां से तेल इत्यादि वस्तुएं निर्यात होती थी। यहां बहुत बड़ी संख्या में कोल्हू की उपलब्धता रही होगी। यह भी हो सकता है कि इस कोल्हू का उपयोग प्राचीन समय में मंदिर परिसर में ही होता रहा होगा।

ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में धुत मिला आरक्षक

माही की गूंज, उज्जैन।

श्रावण माह के चलते शहर में भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन हेतु उमड़ रहे हैं, ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है। इसी बीच एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां ड्यूटी पर तैनात एक आरक्षक शराब के नशे में धुत पाया गया और उसने श्रद्धालुओं से अभद्र व्यवहार किया।

यह मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर आरक्षक गजेंद्र सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में नजर आ रहा है। वीडियो में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि वह हाथ में डंडा लहराते हुए श्रद्धालुओं से बहसबाजी कर रहा है और उन्हें धमका रहा है।

वीडियो के वायरल होते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और उज्जैन के पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से गजेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भार्गव ने बताया कि वीडियो सामने आया वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आरक्षक गजेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आगे की जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से छेड़छाड़

माही की गूंज, धार।

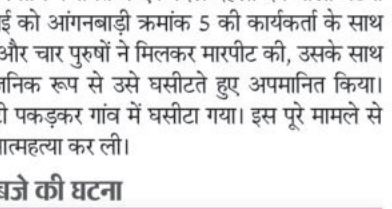

जिले के कानवन गांव में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ मारपीट, छेड़छाड़ और सार्वजनिक रूप से घसीटने की शर्मनाक घटना सामने आई है। इस घटना के बाद पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। दो दिन तक यह मामला दबा रहा, लेकिन महिला की मौत के बाद मीडिया के सामने आया। घटना में शामिल पांच महिलाएं और चार पुरुषों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

धार जिले की कानवन ग्राम पंचायत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 21 जुलाई को आंगनबाड़ी क्रमांक 5 की कार्यकर्ता के साथ गांव की पांच महिलाओं और चार पुरुषों ने मिलकर मारपीट की, उसके साथ अभद्रता की और सार्वजनिक रूप से उसे घसीटते हुए अपमानित किया। बताया गया कि उसे चोटी पकड़कर गांव में घसीटा गया। इस पूरे मामले से आहत होकर महिला ने आत्महत्या कर ली।

21 जुलाई सुबह 9 बजे की घटना

मामला दो दिन तक दबा रहा और 23 जुलाई को पीड़िता की मौत के बाद इसकी जानकारी सार्वजनिक हुई। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 21 जुलाई की सुबह करीब 9 बजे यह घटना हुई। आरोपियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और छेड़छाड़ तक की।

पुलिस ने जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज की

22 जुलाई को पीड़िता ने थाने में आवेदन दिया था। पुलिस ने जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज की। इसी बीच महिला ने आत्महत्या कर ली। उसकी मौत के बाद ही मीडिया को जानकारी मिल पाई। पुलिस ने संगीताबाई, मधुबाला, शुभम सहित कुल नौ लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी।

खाटू श्याम मंदिर में लाखों की चोरी

माही की गूंज, धार।

जिले के धामनोद नगर में एबी रोड स्थित प्रसिद्ध श्री खाटू श्याम मंदिर में बीती रात हुई लाखों की चोरी से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस वारदात ने जहां भक्तों को झकझोर दिया है, वहीं लगातार हो रही चोरियों से लोगों में भारी आक्रोश है।

मंगलवार देर रात करीब 2:05 बजे पांच अज्ञात बदमाश मंदिर के पीछे के रास्ते से अंदर घुसे। चोरों ने भगवान की प्रतिमाओं से चांदी के छह छत्र, लड्डू गोपाल की दो मूर्तियां, दो मुकुट, एक बांसुरी, पांच दानपात्र, कान के कुंडल सहित अन्य कीमती आभूषण चोरी कर लिए। अनुमानित कीमत 20 से 25 लाख रुपए बताई जा रही है।

एक युवक मंदिर में रिकॉर्डिंग करता दिखा था

चोरी के बाद मंदिर के पास खेतों में खाली दानपात्र बरामद हुए हैं। पूरी घटना मंदिर परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई

है, जिसमें पांच नकाबपोश बदमाश साफ नजर आ रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई।

सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि चोरी से एक दिन पहले एक युवक मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग करता दिखा था। साथ ही, दिनभर एक कार मंदिर क्षेत्र में घूमती नजर आई थी।

इस दौरान मंदिर परिसर के बाहर खड़े एक ट्रक चालक के लाइसेंस और नकदी भी चोरी होने की जानकारी मिली है। इधर, धामनोद क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से आमजन में नाराजगी है। श्रद्धालु सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे है।

दिल का दौरा पड़ने से गिर पड़े युवक, फिर डॉक्टर ने किया चमत्कार!

माही की गूंज, उज्जैन।

नागदा शहर में एक डॉक्टर की सजगता और तत्परता ने एक युवक की जान बचा ली। घटना नागदा के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. सुनील चौधरी के क्लीनिक की है, जहाँ 30 वर्षीय एक युवक सीने में दर्द की शिकायत लेकर पहुंचा था।डॉक्टर मरीज की जांच कर ही रहे थे कि तभी युवक अचानक जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया।

मरीज की न तो सांसें चल रही थीं और न ही धड़कनें उसकी हार्टबीट और ब्लड प्रेशर पूरी तरह शून्य हो चुके थे। डॉ. चौधरी और उनकी टीम ने बिना समय गंवाए तत्काल सीपीआर (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) और डीसी शॉक देना शुरू किया। करीब 30 मिनट तक चले इस अथक प्रयास के बाद युवक की धड़कनें वापस लौट आईं। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को इंदौर रेफर किया गया, जहाँ उसकी स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है।

पूरी घटना क्लीनिक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई जो इस जीवन रक्षक प्रयास का साक्षी बन गया। डॉ. सुनील चौधरी ने बताया कि यदि सीपीआर और शॉक समय पर नहीं दिए जाते, तो युवक की जान बचाना मुश्किल था। यह मामला एक बार फिर यह साबित करता है कि समय पर इलाज और चिकित्सकीय तत्परता से जीवन बचाया जा सकता है।

महाकाल की सवारी में देरी से भड़के पुजारी

माही की गूंज, उज्जैन।

श्रावण मास की पहली सवारी में हुई देरी को लेकर महाकाल मंदिर के पुजारी और कहार नाराज हैं। मंदिर समिति द्वारा देरी के लिए पुजारियों और कहारों को जिम्मेदार ठहराने पर विरोध तेज हो गया है। महाकाल मंदिर पुजारियान समिति ने चेतावनी दी है कि यदि अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी, तो आगामी सवारी में पुजारी, पुरोहित और कहार काली पट्टी बांधकर शामिल होंगे।

महाकाल मंदिर पुजारियान समिति के महामंत्री महेश पुजारी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उज्जैन कलेक्टर को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सवारी में देरी प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा थी लेकिन उसका दोष पुजारियों और कहारों पर मढ़ा जा रहा है, जो पूरी तरह अनुचित और अपमानजनक है।

अधिकारी और नेता बना रहे सवारी को प्रचार का माध्यम

महेश पुजारी का कहना है कि बाबा महाकाल की सवारी देश-विदेश से आने वाले भक्तों की आस्था का केंद्र होती है। इसमें सुचारु व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन, पुलिस और मंदिर समिति की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद देरी का ठीकरा उन पुजारियों और कहारों पर फोड़ा गया, जो सदियों से यह धार्मिक परंपरा निभाते आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सवारी मार्ग पर अधिकारी, जनप्रतिनिधि और सवारी में शामिल अन्य लोग पालकी के आगे-आगे चलकर सेल्फी और फोटो खिंचवाते रहे, जिससे सवारी का समय बिगड़ गया। भजन मंडलियां, डीजे, रास मंडलियां और स्वांग रचने वाले लोगों की भीड़ के कारण पालकी के चलने में व्यवधान हुआ, लेकिन इसकी अनदेखी कर पुजारियों को निशाना बनाया जा रहा है।

सीएम से करेंगे मुलाकात, मांगेंगे सम्मान की बहाली

पुजारियान समिति ने स्पष्ट किया है कि जल्द ही पुजारी, पुरोहित और कहार मुख्यमंत्री से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे और उस अधिकारी से माफी की मांग करेंगे, जिसने

तथ्यहीन बयान देकर उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो अगली सवारी में सभी पुजारी, पुरोहित और कहार काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे।

झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई में फिसड्डी साबित हो रहा जिला प्रशासन व पुलिस

आलीराजपुर में हो रही कार्रवाई, झाबुआ जिले में किसी अनहोनी का इंतजार

माही की गूंज, झाबुआ/आलीराजपुर।

वैसे तो जिले में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है लेकिन पुलिस और प्रशासन की मानें तो यहां सबकुछ ऑल इस वेल है। यह बात और है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मंत्रालय में वीसी के जरिये बारिश-बाढ़ व राहत कार्यों की समीक्षा के दौरान जिला कलेक्टर को जमकर फटकार लगाई है। मगर मुख्यमंत्री को चाहिए कि, किसी एक विषय से हटकर प्रदेश के जिलों की एक ऐसी समीक्षा की जाए जिसमें आमजन से जुड़े वे तमाम मुद्दे शामिल हो जो जरूरी है। ऐसी स्थिति में झाबुआ जिले की स्थिति खुलकर सामने आएगी और अंदाजा होगा कि, झाबुआ जिले का आमजन किस तरह की परेशानियों में अपना जीवन यापन कर रहा है। बात शिक्षा, स्वास्थ्य या सुरक्षा की हो जिला सभी में निकम्मे अधिकारियों की बदौलत गर्त में जाता दिखाई दे रहा है।

पिछले दिनों आलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। नतीजा यह निकला कि, आलीराजपुर का सोया प्रशासन हरकत में आया और झोलाछाप बंगालियों, बांगलादेशियों के खिलाफ जमकर महाभियान छेड़ दिया। अब आलीराजपुर जिले के तमाम झोलाछाप बंगाली व बांगलादेशी डॉक्टर भागते फिर रहे है। वैसे इस तरह की कार्रवाई आलीराजपुर जिला प्रशासन को भी किसी के जान से हाथ धोने के बाद नहीं अपितु पहले ही करनी चाहिए थी लेकिन देर आए दुरूस्त आए।

इसके विपरीत अगर बात करें झाबुआ जिले की तो यहां पड़ोसी जिले में इतनी बड़ी घटना होने और प्रशासन की धड़ल्ले से कार्रवाई होने के बावजूद झाबुआ जिले के प्रशासनिक तंत्र या पुलिस के कानों पर अब तक जूं भी नहीं रैंगी है। ऐसा नहीं है कि, झाबुआ जिले में कोई झोलाछाप बंगाली या बांगलादेशी नहीं है। जिले के ग्रामीण इलाकों में इनकी संख्या सैकड़ों में है और वे यहां आम आदिवासी की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए इलाज के नाम पर अपनी जेबें भर रहे है। प्रशासन के जिस तंत्र की जवाबदारी इन्हे रोकने और कार्रवाई करने की है वह अब भी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। हालांकि दबी जुबान में बताने वाले बताते है कि, साहब यह सब सेटिंग का खेल है। प्रशासन में बैठे अधिकारी औपचारिकता पूरी करने के लिए निकलते तो है लेकिन उसके पहले ही झोलाछापों को खबर देकर भगा भी देते है। लेन-देन तगड़ा होने के चलते झोलाछाप डॉक्टर दौरे के दौरान अपने क्लिनिक से रफुचक्कर तो हो जाते लेकिन अगले ही दिन वे खुलेआम अपनी अवैध दुकानें खोलकर बैठ जाते है। झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई भी महज एक ही दिन में पूरी भी हो जाती। जबकि जिले के हर गांव में एक से अधिक झोलाछाप आसानी से अपनी अवैध दुकानदारी चलाते देखे जा सकते है।

पड़ोसी जिले आलीराजपुर में चल रहे घटनाक्रम के बावजूद झाबुआ जिला प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। वह किसी बड़ी घटना के इंतजार में है या किसी के जान गवाने का इंतजार कर रहा है। शायद इसके बाद ही झाबुआ जिला प्रशासन को शर्म आ जाए और वह कार्रवाई के लिए निकल पड़े। मगर अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिले में छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक भ्रष्टाचार की गंगा में डूबकी लगाने में व्यस्त है। इसके लिए प्रमाण की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आए दिन प्रशासनिक नुमाईंदों की कारस्तानियां अखबारों के पन्ने भर रही है।

माही की गूंज पिछले लंबे समय से इस ओर अंधे, गूंगे, बहरे बने प्रशासन को ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्थितियां ढाक के तीन पात ही साबित हो रही है। झोलाछाप डॉक्टरों के साथ -साथ जिले में अवैध बांगलादेशियों के होने के प्रमाण भी माही की गूंज बहुत पहले ही दे चुका है, लेकिन जिला प्रशासन और उसमें बैठे अधिकारियों की इस ओर शायद कोई रूचि दिखाई नहीं पड़ती। जिला प्रशासन का स्वास्थ्य अमला महज खानापुर्ति करता रहता है और बंगाली व बांगलादेशी झोलाछाप डॉक्टरों से भेंट पूजा और चढ़ावा लेता रहता है। इस भ्रष्टाचार में जिले के आला अधिकारियों की संलिप्तता से भी इंकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर यह उच्च अधिकारी ठान ले तो फिर अधिनस्तों को तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, लेकिन उच्चाधिकारियों का ढुलमुल रवैया कई शंकाओं को जन्म देता दिखाई पड़ रहा है। कम से कम झोलाछापों पर ना होने वाली कार्रवाई तो यही दर्शाती है।

जिले में सरकारी स्वास्थ सेवाओं की स्थिति भी इतनी लचर है कि, ग्रामीण अंचलों में चिकित्सालयों के या तो ताले नहीं खुलते या फिर खुलते भी है तो उन स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर ही नहीं है। इस तरह ग्रामीणों को किसी भी आपात स्थिति के लिए जिला मुख्यालय या तहसील मुख्यालय के स्वास्थ्य केंद्रों पर रेफर कर दिया जाता है। जिले की जनता भी इस बात से बाकिफ हो चुकी है कि, सरकारी अस्पताल यानि मरीजों के लिए रेफर केंद्र। वे इस असुविधा से बचने के लिए मजबूरन झोलाछापों की शरण लेते और अपनी ही जान के साथ खिलवाड़ करते दिखाई देते है। हालांकि वर्तमान में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना झाबुआ जिले में देखने को नहीं मिली है लेकिन झोलाछापों की कारस्तानियों और उनके हाथों जान गवाने वालों की फहरिस्त जिले में भी बहुत लंबी है।

कहते है कि, सर्तक रहकर आने वाली समस्याओं से निपटा जा सकता है, लेकिन जिला प्रशासन और उसका स्वास्थ्य अमला पड़ोसी जिले में चल रहे घटनाक्रम के बावजूद कुंभकर्णी नींद निकाल रहा है। अब मुख्यमंत्री यादव को चाहिए कि, प्रदेश के सभी जिलों में न सही लेकिन कम से कम झाबुआ-आलीराजपुर जिले में झोलाछाप डॉक्टरों की अवैध दुकानों व उनसे होने वाली जनहानि की भी एक समीक्षा जरूर करें ताकि सरकार के सामने भी यह स्पष्ट हो जाए कि, सरकारी तंत्र जिले में किस तरह औपचारिकताएं निभा रहा है और आमजन की जान को लेकर कितना चिंतत है या खिलवाड़ कर रहा है। फिलहाल झाबुआ जिला प्रशासन और पुलिस इस मुद्दे को लेकर फिसड्डी ही साबित हो रहा है।

वैसे यहां यह कहा जा सकता है कि, शायद यह मुद्दा पुलिस व उसके महकमें के कार्यक्षेत्र का नहीं है, लेकिन हम यह कहते है कि, आखिर पुलिस जिले में वह सारे काम कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र के नहीं है तो फिर झोलाछाप बंगाली और बांगलादेशियों के खिलाफ कार्रवाई भी इसी श्रेणी में आते है। तो यह स्पष्ट है कि, पुलिस को इस और भी ध्यान देना चाहिए। नशा मुक्ति अभियान हो या और भी ऐसे कई अभियान जो पुलिस ने छेड़ रखे है वैसे ही झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ भी एक अभियान और सही...। वैसे भी जिन कामों को करके पुलिस महकमा और उनके कप्तान अपनी सर्विस बुक के अंक बढ़ाने या तमगे हासिल करने की कोशिश कर रहे है, वह उद्देश्य तो यहां भी पूरा हो सकता है। अगर जिले से पुलिस, झोलाछाप डाक्टरों का सफाया कर देती है तो यह भी अपराधों को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

हालांकि माही की गूंज हमेशा से ही गंभीर मुद्दों पर पुलिस व प्रशासन को घेरता आया है और आगे भी हम अपनी भूमिका आमजन के हितो के लिए यूं ही अदा करते रहेंगें, लेकिन प्रशासन व पुलिस में बैठे आला अधिकारियों को यह रास नहीं आता है। अपने खिलाफ छपी खबरों का विश्लेषण करने की बजाय वे पत्रकारों पर शिकंजा कसने की कवायदों में लग जाते है और कई तरह के झुठे व गंभीर मामलों में उन्हे फंसा कर मामले व रिपोंटें दर्ज कर आरोपी बना दिया जाता है। हालांकि यह प्रशासन और पुलिस का एक स्वांग ही है जो समय आने पर टूट ही जाएगा। मगर माही की गूंज पिछले कई वर्षों से अपने कर्तव्य पथ पर अडिंग होकर चल रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। फिर चाहे किसी को बुरा लगे या भला...।

अतिथि भर्ती में अलग-अलग नियमों से अभ्यर्थी परेशान

कही पुराने अतिथियों को मौका तो कहीं नए सिरे से आवेदन की मांग

माही की गूंज, पेटलावद।
राकेश गेहलोत

शासन की लचर और लड़खड़ाती व्यवस्था को अतिथि नाम की बैसाखी का सहारा देने के लिये नवीन शिक्षा सत्र की माकूल व्यवस्था के अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने की प्रक्रिया फिलहाल ट्राइबल विभाग में की जा रही है। वर्तमान में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो अतिथि शिक्षक पर पूर्व से कार्य कर रहे और जो नये आवेदक अलग-अलग नियमों के चलते परेशानी उठा रहे है। अतिथि भर्ती को लेकर संकुल प्रचार्यो सहित खण्ड शिक्षा अधिकारी की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक मंगलवार को खण्ड शिक्षा अधिकारी डीके ओझा के पास अतिथि शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नहारसिह राणा के नेतृत्व में आवेदन लेकर पहुँचे ओर पूर्व से कार्य कर रहे अतिथियो को नये सिरे से आवेदन करने के नियम पर विरोध जताया ।

-बीईओ कार्यालय पेटलावद

बीईओ और संकुल प्राचार्य आलाप रहे अपनी ढपली अपना राग

एक और बीईओ खण्ड शिक्षा अधिकारी पेटलावद डीके ओझा ने अपने कार्यकाल पर पूरे विकास खण्ड में रिक्त पड़े पदों की सूची लगा कर नये सिरे से आवेदन आर्मत्रित कर लिये। साथ ही एक समिति भी खण्ड शिक्षा अधिकारी ने बनाई जो अतिथि शिक्षक पद के लिए आने वाले आवेदनों की जांच करेगी। खण्ड शिक्षा अधिकारी ने जो नियम लागू किया है, उसके अनुसार संकुल क्षेत्र में जहा भी अतिथि शिक्षक के पद खाली है वहा नये सिरे से आवेदन किये जायेंगे। उक्त नये नियम से पूर्व से कार्य कर रहे अतिथि शिक्षको में आक्रोश है ।

अतिथि शिक्षको ने दिया आवेदन

खण्ड शिक्षा अधिकारी के द्वारा नये सिरे से भर्ती के नियम से पूर्व से कार्य कर रहै अतिथि शिक्षको में रोष है। उनका कहना है कि, 10 से 15 वर्षो से अतिथि शिक्षक के रूप में दो हजार के वेतन से सेवाएं देते आ रहे है और नये नियमो से हर पद पर नये लोग आवेदन करेगे। क्योकि सरकार ने वेतन बड़ा दिया जिससे नये लोग आवेदन करेगे जो हमारे साथ अन्याय है । इस नियम के व विरोध में अतिथि शिक्षको ने बीईओ ओझा को आवेदन देकर पूर्व से कार्य कर रहे अतिथि शिक्षको को ही प्राथमिकता देने की मांग की है।

बीईओ डीके ओझा ने बताया कि, शासन के नियमो के अनुसार नियुक्ति की जाएगी ।

शासन की गाइड लाइन का हवाला पर संकुल प्राचार्य अपने नियमो से कर रहे कार्य

उधर बीईओ अपनी ढपली बजा रहे है तो दूसरी और संकुल प्राचार्य अपने अलग नियमो से कार्य कर रहे है। विकास खण्ड के कुछ संकुल प्रचार्यो ने शासन के नियमो और हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षको को ही रखा और स्कूल में पद नही होने का हवाला दिया जा रहा। वही उन्ही स्कूलों में पद रिक्त बता कर बीईओ कार्यालय में आवेदन बुलवाए जा रहे है ।

अलग-अलग बयान

शासन के नियमो से कार्य होगा, सभी को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, पूर्व से कार्य कर रहे अतिथियो को भी नये सिरे से आवेदन करना होंगे, आवेदन के अनुसार मेरिट सूची बनेगी - खण्ड शिक्षा अधिकारी डीके ओझा।

शासन के नियमो में साफ लिखा है कि पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षको की भर्ती की जाए और उनके द्वारा सहमति से पद छोड़ने की स्थिति में स्कोर कार्ड अनुसार दूसरे नम्बर रहे अभ्यर्थी को मौका दिया जा। शासन के नियमो में हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन का भी कहा गया जिसके तहत कार्यरत अतिथि शिक्षकों को पहली पात्रता देनी है - एम मालवीय प्राचार्य बरवेट संकुल।

2007 से अतिथि शिक्षक पद पर कार्यरत।

हमारे संकुल में सभी अतिथि के रिक्त पदों पर आवेदन लिए जा रहे है जो पूर्व से कार्यरत है उनसे भी नये सिरे से आवेदन लिए जा रहे है। सभी आवेदन जांच के लिए बीईओ कार्यालय जायेगें, लेकिन पूर्व से कार्यरत अतिथियो को प्राथमिकता रहेगी - देवेंद्र राका प्राचार्य जामली संकुल।

अतिथि शिक्षकों को लेकर चल रही मन मानी , भर्ती के नाम पर लेन-देन

विकास खण्ड अधिकारी सहित विकास खण्ड के संकुल प्रचार्यो के बयान भी अलग-अलग जा रहे है । अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में दावेदार सीधे ही प्रचार्यो से सम्पर्क करते है और नोकरी हासिल करने के लिए लेन-देन ओर दबाव, प्रभाओ का प्रयोग करते है । कई स्थानों पर प्राचार्य अपने चहतो को अतिथि के पद पर लगाने के लिए कई तरह की हेरा फेरी करते है । दोहरे नियमो का उपयोग भी प्रचार्यो द्वारा अपने हित के लिए किया जा रहा है। कई पदों पर नए सिरे से आवेदन लेने की बात की जा रही तो उसी संकुल में कुछ कारण देकर एक-दो पदों को भरा हुआ बता कर आवेदन स्वीकार करने से मना किया जा रहा है। फिलहाल नये और अलग-अलग नियमो के चलते अभ्यथियों की फजीयत हो रही है और जो लोग वर्षो से अतिथि पद पर कार्य कर रहे है उनको संकुल में रिक्त पद के हिसाब से आवेदन करने जाना पड़ रहा है।

एनआरबी ट्रांसपोर्ट की मनमानी, डेली सर्विस के नाम पर धोखाधड़ी...!

माही की गूंज,
सुनील सोलंकी।

किसी समय में वैभव ट्रांसपोर्ट के नाम से प्रचलित यह ट्रांसपोर्ट अपनी मनमानी व लापरवाही के चलते इंदौर से लेकर पेटलावद व खवासा तक प्रचलित है। वहीं अपनी अनियमितताओं को दबाने और डेली सर्विस के नाम पर परिवहन विभाग से एनआरबी ट्रांसपोर्ट के नाम पर अनुबंध कर वैभव ट्रांसपोर्ट के स्थान पर एनआरबी ट्रांसपोर्ट नया नाम रख अब भी डेली सर्विस के नाम पर उक्त ट्रांसपोर्ट द्वारा अपनी मनमानी के साथ धोखाधड़ी व्यापारियो के साथ की जा रही है।

उक्त ट्रांसपोर्ट इंदौर व पेटलावद में कार्यालय के साथ संचालित हो रहा है। उक्त ट्रांसपोर्ट इंदौर से डेली सर्विस के अनुबंध के साथ पेटलावद तहसील क्षेत्र व खवासा तक माल ढोने का काम करता रहा है। खवासा-बामनिया तक इंदौर से माल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आने की व्यवस्था पूर्व वर्षो में इसी एक ट्रांसपोंटर की रही है। वहीं वर्तमान में एक अन्य ट्रांसपोर्ट डेली सर्विस के नाम पर इंदौर से पेटलावद क्षेत्र एवं खवासा तक माल ढो रहा है।

अन्य उक्त ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था से व्यापारी कहीं न कहीं संतुष्ट भी है। वही वैभव ट्रांसपोर्ट की मनमानी ऐसी की वह डेली सर्विस के नाम पर कई -कई दिनों तक माल की डिलीवरी व्यापारी को नहीं करता है। ऐसे में कई सामग्री ऐसी होती है कि जो की सीजनल के हिसाब से होकर एक दिन या एक सप्ताह या एक पखवाड़े या उस महीने में ही बिक्री हो सकती है। अन्यथा उक्त सामग्री व्यापारी को माल रिसीव के दूसरे दिन नहीं मिलने पर कई बार व्यापारियों को एनआरबी ट्रांसपोर्ट की वजह से बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। जो कई बार विवाद का कारण भी बनता रहा है। लेकिन ट्रांसपोर्ट द्वारा हमेशा गुमराह कर सर्विस में कोई सुधार नहीं किया गया।

इतना ही नहीं उक्त ट्रांसपोर्ट द्वारा माल डिलीवरी में लंबा समय करने के साथ माल आ रहा है कह कर आज-कल कर महीने बाद कहता है कि, आपका माल गुम हो गया है और समझौते के नाम पर आधे-अधूरे पैसे देने की बात मालिक व मुलाजिम कर भी देते हैं तो, वह व्यापारी को आजकल कर महीना व महीने से कई वर्ष निकाल देते हैं और गुमराह करते हुए व्यापारी को पैसा नहीं देते हैं।

नियम अनुसार माने तो डेली सर्विस के नाम पर जो अनुबंध ट्रांसपोर्ट द्वारा किया जाता है उस अनुबंध के हिसाब से कोई भी ट्रांसपोर्ट कार्य नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वही माल में डिलीवरी में देरी होने पर भी व्यापारी या किसी भी व्यक्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई ट्रांसपोर्ट को करना होती है। एसे में तय है सीजनल सामग्री अगर किसी व्यापारी या व्यक्ति को नहीं मिले तो उसके व्यापार में नुकसान के साथ उस समान का क्या करें? जो बाद में न हीं कोई विक्रय होगा। ऐसे में उस माल को एक वर्ष तक रखना व दोहरी नुकसानी का सामना ट्रांसपोर्ट की मनमानी के साथ व्यापारिक को झेलना पड़ता है। तथा उक्त तरह की नुकसानी एनआरबी ट्रांसपोर्ट की मनमानी के साथ कई व्यापारियों को नुकसानी झेलना पड़ी है।

28 जून को एनआरबी ट्रांसपोर्ट इंदौर ने छपी किताबों का एक बंडल किया रिसीव।

12 जुलाई को छपी किताबों के दो बंडल रिसीव किये लेकिन ट्रांसपोर्ट द्वारा कॉपी के दो बंडल उल्लेख किया।

एक मामला खवासा से यह सामने आया कि, करीब 4 वर्ष पूर्व दीपावली के दौरान शासन के निर्देश पर नियत स्थान पर लाइसेंस लेकर पटाखा विक्रय करने वाले व्यापारी के दो पटाखा कार्टून जिसका मूल्य करीब 30 हज़ार से ऊपर था उक्त माल 4 वर्ष पूर्व दीपावली के दिन तक भी आज आ रहा है, अभी आ रहा है कह कर पेटलावद एनआरबी ट्रांसपोर्ट पर पदस्थ मुलाजिम केसु नाम का व्यक्ति कहता रहा लेकिन माल नहीं दिया। वहीं दीपावली के महिने के बाद कहा कि, माल कहीं गुम हो गया में मैं 30-35 हज़ार तो नहीं बल्कि 20 हज़ार रुपये दे दूंगा केसू ने कहा। मरता क्या नहीं करता की तर्ज पर व्यापारी अपने मूलधन से भी कम राशि 20 हज़ार लेने को तैयार हो गया लेकिन वह पैसा आज तक 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी केसू नाम के इस मुलाजिम ने नहीं दिया। वहीं उक्त जानकारी मालिक हंजा भंडारी को भी दी गई लेकिन उसका कोई समाधान नहीं किया। ऐसे में अब व्यापारी अपने माल आने वाले भाड़े में एनआरबी ट्रांसपोर्ट से अब तक 5 से 6 हज़ार के करीब काट चुका है। अब भी यह व्यापारी 14 से 15 हज़ार रुपये युक्त ट्रांसपोंटर से मांग रहा है।

ट्रांसपोर्ट से माल गुम होने की बात करें तो वह तो सही नहीं माना जा सकता ऐसे में यह माना जा सकता है कि, ट्रांसपोर्ट के यह संचालक कहीं न कहीं सामग्री चोरी कर अन्य को बेच दिया जाता है और बाद में गुम होने का कह कर उक्त तर्ज पर गुमराह कर व्यापारी को पैसा नहीं दिया जाता है।

यह तो रही 4 वर्ष पूर्व व एनआरबी ट्रांसपोर्ट की मनमानी की बात पर उसी व्यापारी के 3 छपी किताबों के बंडल अब भी एनआरबी ट्रांसपोर्ट द्वारा नहीं दिया जा रहा है। बता दे कि, शासकीय प्रिंट से छपी यह किताबें मिनिमम मार्जिन के साथ मिलती है और उक्त किताबें क्षेत्र में नए सत्र में स्कूल 16 जून से खुलने से लेकर अंतिम जुलाई माह तक बिकती है। ऐसे में खवासा के उसी व्यापारी जिसका पैसा 4 साल से एनआरबी ट्रांसपोर्ट से मांग रहा है उसी व्यापारी की किताबें जिसमें छपी किताबो का एक बंडल 28 जून 2025 को बिल्टी नंबर 32947 पर इंदौर व्यापारी से रिसीव एनआरबी ट्रांसपोर्ट ने किया। वहीं 2 छपी पुस्तकों का बंडल 12 जुलाई 2025 को बिल्टी नंबर 33673 से एनआरबी ट्रांसपोर्ट ने रिसीव किये।

उक्त दो बंडल वाली बिल्टी पर अपनी मन मर्जी के साथ छपी किताबों के स्थान पर दो कॉपी बंडल लिखा है। उक्त तीनों बंडल व्यापारी को समय पर नहीं मिलने पर ट्रांसपोर्ट के मालिक हंजा भंडारी के व्हाट्सएप 9926544800 पर मय बिल्टी के साथ 17 जुलाई को मैसेज भी किए गए। तथा उसके बाद भी मैसेज किए गए लेकिन आज तक छपी किताब की महंगी किताबें के यह तीन बंडल आज तक खवासा के व्यापारी को नहीं मिले। वहीं टेलिफोनिक चर्चा भी हंजा भंडारी व मुलाजिम केसू व अन्य के साथ होने के बाद भी आज तक यह किताबो के तीन बंडल व्यापारी को नहीं मिले। वहीं टेलीफोन पर हंजा भंडारी यह जरूर कहता रहा कि, किसी भी स्थिति में किसी का माल नहीं रोका जा सकता है लेकिन अब तक कोई समाधान ट्रांसपोर्टर द्वारा नहीं किया गया। ऐसे में अब व्यापारी का कहना है कि, मय हर्जाने के साथ ट्रांसपोर्ट के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है कि ट्रांसपोर्टर इस बार अपनी मनमानी व व्यापारी के साथ की जाने वाली धोखाधड़ी को किस तरह से पटाशेप करने का प्रयास करेगें! चोरी या स्वयं द्वारा गुम की गई किताबे कितने दिनो बाद व क्या कह कर एनआरबी ट्रांसपोर्टर देता है यह बाद में ही पता चलेगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422